



दुर्ग के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान

दुर्ग। भिलाई के हाथखोज स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण आसपास के क्षेत्र में अंधरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल को दी जिसके बाद दमकल को टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुटी हैं। पुरानी भिलाई के हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि श्याम केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर कैमिकल रखा जा बतया जा रहा है कि वेस्टिंग के दौरान नकली जिगारी केमिकल वाले ड्रम तक पहुंची और आग भड़क गई। फैक्ट्री में कैमिकल से भरे ड्रम में जिगारी का संपर्क होने से आग लगी है। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जारी है। घटना में कोई भी हानाहत नहीं हुआ है। इस आग से फैक्ट्री को नुकसान हुआ है सीएसपी छवनी आग के कारण मौके पर काम कर रहे कुछ मजदूर फंस गए थे। जिन्हें बड़ी मशकत के बाद बाहर निकला गया। आग की सूचना पर जिला प्रशासन, एसीसी और बीएसपी के दमकल की गाड़ियां मौक पर पहुंचकर आग बुझाने का काम कर रही है। घटना की सूचना मिलने पर छवनी सीएसपी और पुरानी भिलाई की टीम भी मौके पर पहुंची। आग से फैक्ट्री में लाखों का नुकसान होने का अंदेश है।

कोमाखान जंगल में फिर तेंदुआ दिखने से दहशत

महासमुंद । महासमुंद जिले के कोमाखात क्षेत्र में तेंदुए की महत्वात अभी खत्म नहीं हुई है। झिटकी गांव में घर में घुसकर एक ही परिवार के छह लोगों को घायल करने वाले तेंदुए की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं इसी क्षेत्र में दूसरा तेंदुआ दिखा है, जिसके बाद ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। बुधवार को झिटकी से लगे कारीपाट के दादरखार जंगल में एक ग्रामीण ने तेंदुए को अपनी आंखों के सामने देखा। तेंदुआ दिखते ही ग्रामीण अपनी बकरियां जंगल में छोड़कर भाग गया। घटना के बाद से झिटकी सहित आसपास के जंगल से लगे गांवों में एक बार फिर डर का माहौल है। ग्रामीणों को अब जंगल जाने और अपने मवेशियों को चराने में भी डर लग रहा है। खासकर उन रास्तों पर जहां से ग्रामीणों रोजाना जंगल की ओर आते-जाते हैं, वहां लोगों की आवाजही कम हो गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर करीब 1 बजे झिटकी निवासी नन्दराम चक्रधारी अपनी बकरियां चराने के लिए दादरखार जंगल की ओर गया था। वो जंगल के अंदर नाले के पास पहुंचा ही था कि उसकी नजर कुछ दूरी पर बैठे तेंदुए पर पड़ी। अचानक सामने तेंदुए को देखकर नन्दराम घबरा गया। उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ तो वह बिना देर किए बकरियों को वहां छोड़कर गांव की तरफ भाग निकला। ग्रामीण के अचानक वापस आने और घटना की जानकारी देने के बाद गांव में भी हड़कंप मच गया।

कलेक्टर और सीईओ ने निर्माणाधीन कलेक्टर कार्यालय, जिप भवन, आंगनबाड़ी केंद्र आदि का किया औचक निरीक्षण



अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समय-सीमा में निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रमती जेन ने कहा कि शासकीय भवनों का निर्माण जन्हित से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता एवं तकनीकी मापदंडों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने तथा कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनवश्यक विलंब नहीं किए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और सीईओ ने निर्माणाधीन भवनों में आवश्यक व्यवस्थाओं, कार्य की प्रगति तथा मौके पर उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की

सतत मॉनिटरिंग करने और निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि भवनों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण एवं उपयोगी रूप से समय पर पूरा हो सके। इसी क्रम में सकरेली बाराद्वार स्थित नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का अवलोकन किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य करने तथा भवन निर्माण को समय-सही में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, इसलिए भवन निर्माण में गुणवत्ता एवं आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के

धूमतरी में अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन का बड़ा एक्शन



विभाग की कार्रवाई केवल दो दिनों तक सीमित नहीं है। 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक 341 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें करबा गंगा 18 लाख रुपये खनिज मद में जमा कराया गए हैं। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और अवैध खनन के मामलों में वाहन और मशीनरी जब्त की गई है। इसमें ट्रैक्टर, हाईवा और चैन माउंटन जैसी मशीनों पर भी कार्रवाई शामिल है। खनिज विभाग की टीम लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में जांच कर रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि बिना अनुमति रेत का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सर्वेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ वाहनों के दस्तावेज और खनिज परिवहन से संबंधित वैध अनुमति की जांच की जा रही है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने अधिकारियों को अवैध खनिज गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने की निर्देश दिए हैं।

म लिखे पर्चे फेंककर दहशत की कोशिश, 2 गिरफ्तार



का माहौल बनाने की योजना बनाई। दोनों ने धमकीपूर्ण पत्रों तैयार कर मुरदण्ड से पकड़ाछड़ जाते वाले रास्ते पर फेंके। पुलिस ने संधीप मड़कम और नांगेश बोड़के को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ जनसुरक्षा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है। बीजापुर निवासियों से अपील है कि यदि उन्हें कोई माओवादी पत्रों या ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधों या ऐसी कोई अफवाहों सुनने में आती है तो उस पर यकीन न करें और भ्रमित होने की जगह तुरंत पुलिस को जानकारी दें। बीजापुर पुलिस अधिकारी ने असाभाजिक तत्वों को चेतावनी दी है कि माओवादी का आडू में किसी को डराने धमकाने या शासकीय गतिविधियों में बाधा पहुंचाने का प्रयास न करें। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाज में भय का वातावरण पैदा करने वालों के खिलाफ पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा की कार्रवाई



सक्ती। कलेक्टर श्रीमती यश्री जैन के निदेशन पर जिले खनिजों के अवैध उत्खनन पर परिवहन के विरुद्ध खनिज भाग द्वारा लगातार कार्रवाई जा रही है। इसी क्रम में श्री जस कुमार धुव, खनिज निरीक्षक एवं खनिज विभाग इन्सपेक्टर द्वारा विगत दिनों ग्राम अनियाकला क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन के 03 प्रकरण, 15 नॉक 06 अक्टूबर 2026 को म म बारगाढ़ नगर क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन के 02 प्रकरण गा ग्राम चन्द्रपुर नगर क्षेत्र में 01 ट्टी के अवैध परिवहन के 01 प्रकरण में कार्रवाई की गई। 15 कार्रवाई के दौरान कुल 06 वाहनों, हाईवा एवं ट्रैक्टरों को जब्त कर संबंधित वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा केन्द्र सकी, थाना बारगाढ़ एवं थाना चन्द्रपुर में सुरक्षा रखी गया है। जब्त वाहनों के संबंध में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध खनिज अमले द्वारा सतत निगरानी रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।

वाहनों, हाईवा एवं ट्रेक्टरों को जब्त कर संबंधित वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा केन्द्र सचो, थाना बाराहाइ एवं थाना चन्द्रपुर में सुरक्षार्थ रखा गया है। जब्त वाहनों के संबंध में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध खनिज अमले द्वारा सतत निगरानी रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

जरिए लाफिन कला के ग्रामीणों ने बदल दी गांव का दशा-दिशा

महासमुंद। महासमुंद जिले के ग्राम लाफिन कला के ग्रामीणों ने जनसहयोग की ऐसी मिसाल पेश की है, जो दूसरे गांवों के लिए भी प्रेरणा है। गांव के ग्रामीण विकास कार्यों के लिए सरकारी बजट का इंतजार करने के बजाय आपसी सहयोग और ग्राम फंड से अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। ग्रामीणों का ध्येय वाक्य है— अपना काम खुद कर लो। करीब 1200 की आबादी वाले लाफिन कला में ग्रामीणों ने जनसहयोग से मंदिर निर्माण, कच्ची सड़कों का मुरुमीकरण, कांक्रिट सड़क और गौठान सहित कई विकास कार्य कराए हैं। अब करीब 40 हजार वर्गफीट के गौठान को कांक्रिट करने का काम ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। ग्राम लाफिन कला के ग्रामीणों ने कि गांव की समस्याओं के समाधान के लिए शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से राशि मिलने का इंतजार करने में काफी समय लग जाता है। ऐसे में ग्रामीणों ने मिलकर गांव के विकास की ज़िम्मेदारी खुद उठाई है। जनसहयोग और ग्राम फंड से गांव में अब तक कई छोटे-बड़े विकास कार्य कराए जा चुके हैं।

पुलिसकर्मियों पर नशे में मारपीट का आरोप

पूरजपुर। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर पुलिस एक ऑफिस से निवादीं में है। पुलिस पर शराब के पीने में कथित मारपीट और बदसलूकी करने के आरोप लगे हैं। पीड़ितों ने स्कॉर्ऑफिस में निशिकायत की है, जिसके बाद इस मामले में गांव के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। सल, चन्द्रमेढ्रा गांव के रहने वाला विजय दुबे की मां उर्मिला दुबे के साथ शिकायत करने की कार्याल सूरजपुर पहुंचा। पीड़ित का प है कि वह जब अपने घर से जर्ही की ओर रहा था, तभी रास्ते में पलमा चौक पर चंद्रांग के पुलिसकर्मी आने वाले वाहनों की जाँच कर रहे थे। वहीं जब पीड़ित उनके पास जा तो वह किसी बात को लेकर नाराज हो गए। ज्यादा बोलता है कि बात करते हुए उसके मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में उसके में गम्भीर चोट आई है। वहीं शराब के नशे में पीड़ित की मां के साथ भी पुलिसकर्मीयों की से मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप स घटना के बाद माफी मांगते पुलिसकर्मी का नश्यो भी सामने आया है।

बस्तर से गहरा नाता रहा नाना पाटेकर का, शोक की लहर

जगदलपुर। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से बस्तर के कलाकार जगत में भी शोक की लहर है। नाना पाटेकर का बस्तर से पुराना और खास जुड़ाव रहा है। बस्तर से अभिनेता नाना पाटेकर का लगान था। वे वर्ष 1987-88 के दौरान दो बार बस्तर आए थे। बताया जाता है कि नाना पाटेकर ने धरमपुरा स्थित इंजीनियरिंग कालेज में समय बिताया था। इसके अलावा वे करीब एक महीने तक बस्तर में फिल्म शूटिंग के सिलसिले में रहे। इस दौरान फिल्म आज की महाभारत की शूटिंग बस्तर की खूबसूरत वादियों में की गई थी। फिल्म में नाना पाटेकर के साथ सुरेश ओबेरॉय, दीप्ती नवल, भारत भूषण, नीता पुरी सहित कई अन्य कलाकार भी बस्तर पहुंचे थे। अभिनेता नाना पाटेकर नक्सलवाद का प्रचुर बनी फिल्म में काम करने के पहले वे बस्तर के धुर नक्सल इलाकों में भ्रमण कर जमीनी स्थिति का पता करते थे। गंगा प्रोडक्शन की फिल्म आज की महाभारत की शूटिंग बस्तर की खूबसूरत वादियों में की गई थी। बस्तर के उड़ीसा बॉर्डर से लगे धनुषी देवड़ा मंदिर चित्रकटो, तीर्थराढ़, नया मुंडा एवं जगदलपुर शहर के कुछ स्थानों में शूटिंग की गई थी।

इंद्रावती टाइगर रिजर्व का पहचान चिन्ह तैयार 15 अक्टूबर तक

बीजापुर। वन्यजीव सप्ताह 2026 के अवसर पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर का पहचान चिन्ह तैयार करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। पहचान चिन्ह (लोगो) में इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र की पहचान और यहां पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीवों को दर्शाना होगा। डिजाइन में बाघ, वन में बैसा और ऊदबिलवा को प्रमुखता से शामिल करना अनिवार्य है। साथ ही लोगो में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर, छत्तीसगढ़ का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पहचान चिन्ह (लोगो) में राममुद्रा अथवा अशोक स्तंभ का उपयोग नहीं किया जाना है। प्रतियोगिका के लिए लोगो का डिजाइन सरल, आकर्षक और विभिन्न आकारों में स्पष्ट दिखाई देने वाला होना चाहिए। प्रतिभागियों को पहचान चिन्ह की सॉफ्ट कॉपी के साथ उसका प्रपोज़न रैशियो अथवा लंबाई-चौड़ाई दर्शाने वाली फाइल भी जमा करनी होगी। यदि पहचान चिन्ह एआई के माध्यम से तैयार किया गया है।

प्रधान आरक्षक की पत्नी-बेटी की हत्याकांड मामले में 3 को फांसी की सजा

सूरजपुर। प्रधान आरक्षक की पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की धारदार हाथियार से हत्या करने के बाद दोनों का शव खेत में निर्वस्त्र हालत में फेंके जाने वाले तीन आरोपियों को जिसमें मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, पूर्व एनएसआई जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके, फूल सिंह उर्फ रिकू को फंसी की सजा सुनाई, जबकि चौथे दोषी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियार ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सुनावी के बाद न्यायालय ने सूरज साहू आर्यन, निलकंठ साहू को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई सूरजपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। कोर्ट ने 28 सितंबर को 4 आरोपियों को दोषी पाया था और फैसला 8 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान काफी गमगाहमी की स्थिति रही। उल्लेखनीय है कि सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की 13 अक्टूबर 2024 की रात नृशंस हत्या कर दी गई थी।

स्टाफ नर्सों के ग्रेड-पे बढ़ाने की मांग ने पकड़ा जोर, 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन

सुकमा। छत्तीसगढ़ में स्टाफ नर्सों एवं नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों के ग्रेड पे बढ़ाने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। सुकुमा नर्सिंग संघ ने ग्रेड पे एवं वेतनमांग पर वृद्धि करने की मांग की है। इसे लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। संगठन ने मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में सरकारबद्ध आंदोलन की घोषणा भी की है। नर्सिंग संघ का कहना है कि 2018 में ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन किया गया था। इसके बाद शासन स्तर पर कमेट्री का गठन कर ग्रेड पे में वृद्धि को लेकर अनुसंधान के गई थीं, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद इन अनुसंधानों को लागू नहीं किया गया। 2023 में भी छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले नर्सिंग कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, लेकिन संगठन के अनुसार अब तक मांग का निराकरण नहीं हो सका है। नर्सिंग संगठनों के मताधिक ग्रेड-पे सहित कई



मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री सहित कई मंत्री-सांसदों को भी आवेदन दिया जा चुका है। संगठन का दावा है कि लगातार मांग उठाने के बावजूद सरकारात्मक निर्णय नहीं होने के कारण प्रदेशभर के नर्सिंग कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। आवेदन के अनुसार वर्तमान में प्रत्येक के स्टफ नर्सों को 2800 ग्रेड पे के तलब वेतन मिल रहा है। संशु का तर्क है कि थिएटर, शिशु संवेदनशील की भूमिका और दिन-रात देते हुए को 24

सिंस कर्मचारियों की शैक्षणिक जा रहा
योग्यता, कार्य की प्रकृति, ग्रेड पे
जन्मदेशारियों और 24 घंटे की निराक
नवाओं को देखते हुए ग्रेड पे में संगठन
द्धि किया जाना जरूरी है। कार्यक
नर्सिंग स्टाफ प्राथमिक और 4
मासादायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला संगठनों
स्पतालों, स्थल अस्पतालों, आयोसि
वहित कई स्वास्थ्य संस्थानों में को रा
द्वारा दे रहा है। ढा अप्रेशन को थो

पातकालीन सेवाओं, मातृ एवं स्वस्थ तथा टीकाकरण जैसे क्षेत्रों में भी नर्सिंग कर्मचारियों का रहती है। संगठन ने अपने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों का उद्धारण वा किया है कि वहां स्टाफ नर्सों को से 74800 तक ग्रेड पे दिया	जिला नर्सिंग धरना-1 इसके ब रायपुर महौरा नहीं हो अनिश्चित चेतावनी
---	---

इसी आधार पर छत्तीसगढ़ में भी होने की मांग की गई है। मांगों के नहीं होने की स्थिति में नर्सिंग के 5 चरणों में आंदोलन का आयोजन किया है। संगठन के अनुसार वर्ष 2026 को रायपुर में नर्सिंग पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक की जाएगी। इसके बाद 5 अक्टूबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और 7 अक्टूबर को अवकाश के दौरान ब्लॉक एवं राज्य पर स्वास्थ्य संस्थानों के बाहर धरान का कार्यक्रम खरा गया है। 30 अक्टूबर 2026 को राजधानी प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन एवं स्वावित है। संगठन ने मांग पूरी की स्थिति में 18 नवंबर 2026 से आंदोलन आंदोलन शुरू करने की भी है।



धमतरी धमतरी पुलिस ने पेट्रोल पंप परिसर में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की बेटी पेट्रोल पंप के सामने खुले नाले में गिर गई थी और उसकी बहकूर मौत हो गई थी, जिससे वह आक्रोशित था। इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि स्कंधावना पांडेय के निदेश में जिले में असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विपरीद लगातार प्रभाती वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना मगरलोड पुलिस ने ग्राम मेघा स्थित मातारानी पेट्रोल पंप परिसर में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पूरा मामला मगरलौड थाना क्षेत्र के ग्राम मेधा स्थित मातारानी पेट्रोल पंप का है। आरोपी की पहचान जीवन निषाद (47) निवासी वार्ड क्रमांक 01, मेधा के रूप में हुई है। 1 अक्टूबर की रात करीब 01:30 बजे आरोपी पेट्रोल पंप परिसर में पहुंचा और

पाली-गलौज करते हुए पेट्रोल नोजल में आग लगाने का प्रयास किया। इसमें सफल नहीं होने पर उसने परिसर में खड़ी दो बाइकों को माचिस मारकर मौके से फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट पर थाना मंगरलोड में अपराध क्रमांक 194/2026, धारा 296, 323(2)(एफ) एवं 324(4) भारतीय न्याय संहिता (बोएनपस) के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामला लेडी गंधीभारती को देखते हुए मंगरलोड पुलिस स्टेशन में आरोपी की पतासजी कर उसे गिरफ्तार किया गया। पुछताछ में आरोपी ने बताया कि 26 सितंबर को पेट्रोल पंप के सामने खुले नाले के कारण उसकी बेटी नाले में गिर गई थी और महानदी में आई बाढ़ के पानी में बहकर उसकी मौत हो गई थी। आरोपी इस घटना के लिए पेट्रोल पंप प्रबंधन को ज़िम्मेदार मानता था। इसी बात को लेकर उसके मन में आक्रोश था, जिसके चलते उसने गुस्से में आकर पेट्रोल पंप परिसर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल होने वाली माचिस और घटना के समय पहने गए कपड़े जब्त किया गया है।

इतिहास मोदी सरकार को किस नजर से देखेगा?

विपिन पब्ली

जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात विधानसभा हॉल में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दाखिल हुए, तो यह पहली बार था जब वह बिना कभी विधायक चुने गए विधानसभा में प्रवेश कर रहे थे। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में संसद में उनका प्रवेश भी सदन में उनकी पहली उपस्थिति थी क्योंकि वह कभी सांसद नहीं रहे थे। तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है जब उन्होंने बिना किसी रुकावट के 25 वर्षों तक सरकारों का नेतृत्व करने की अपनी अभूतपूर्व यात्रा शुरू की थी। इस कालंमार्ग की सीमाओं के भीतर सरकारों के मुखिया के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान की सफलताओं और विफलताओं को संक्षेप में बताना भी संभव नहीं होगा। हालांकि, एक अनुमान लगाने का प्रयास किया जा सकता है कि पद छोड़ने के बाद वह किस तरह की विरासत छोड़ेंगे। निश्चित रूप से, इस तरह के किसी भी निष्पक्ष विश्लेषण के आलोचक जरूर होंगे जो व्यक्त किए गए विचारों से सहमत न हों। सबसे पहले उन सकारात्मक पहलों की बात जो पहले गुजरात और फिर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बाकी देश को प्रभावित कर चुकी हैं। यह लेखक उस समय का साक्षी है जब मोदी मुख्यमंत्री के कार्यालय में आए थे। राज्य में प्रगति की गति धीमी थी और अहमदाबाद और वडोदरा के बीच कालंमार्ग और बंदरगाहों के विकास तथा राज्य के कुछ हिस्सों में औद्योगिक विकास को छोड़कर, इसकी अर्थव्यवस्था सुस्त थी। एक चौथाई सदी बाद, गुजरात कई मायनों में बदल गया है। बुनियादी ढांचे, उद्योग और आर्थिक विकास सहित विकास की गति अभूतपूर्व रही है। साबरमती नदी, जो मेरे वहां तेजाब रहने के दौरान एक मैली, सूखी मौसमी नदी में बदल गई थी, अब उसमें साल भर पानी रहता है और एक शानदार रिवरफ्रंट है। राजमाार्गों, बंदरगाहों, आवास, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आया है। वाइब्रेंट गुजरात निवेश शिखर सम्मेलनों, ई.गवर्नेंस पहलों और एक आधुनिक, निवेश के अनुकूल गुजरात की नींव रखने में उनकी भूमिका को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

मोदी ने ‘गुजरात मॉडल’ को राष्ट्रीय राजधानी में लाने की कोशिश की, हालांकि उनके आलोचक इसे सुनने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू कीं। इनमें स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, आयुष्मान भारत और आधार से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार और प्रमुख बुनियादी ढांचे का उन्नयन शामिल है। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसे उनके नारों ने लोगों को प्रभावित किया, हालांकि योजनाओं के कार्यान्वयन में अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। उनका पहला कार्यकाल, स्पष्ट जनादेश के साथ, देश की अर्थव्यवस्था और शासन को बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाओं द्वारा चिह्नित था, जिसमें विवादास्पद विमुद्रीकरण (नोट बंदी) और देश को एक कर प्रणाली के तहत एकीकृत करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का रोल आऊट शामिल था। उनके दूसरे कार्यकाल में, और भी बड़े जनादेश के साथ, अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू और कश्मीर को भारत के संवैधानिक ढांचे में एकीकृत किया गया। इसने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) के पारित होने, कोविड 19 के प्रति प्रतिक्रिया और प्रमुख बुनियादी ढांचे के उन्नयन को भी देखा। उनका तीसरा कार्यकाल, जिसमें भाजपा ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है और परिणामस्वरूप गठबंधन सरकार बनी है, ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ योजना, वक्फ संशोधन कानून और जाति जनगणना की दिशा में कदम पर सक्रिय विचार के साथ प्रगति पर है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

16 दर्शन, मीमांसा और फिलासफी

गतांक से आगे...

दर्शन शब्द का शब्दार्थ है देखना अर्थात् साक्षात् रूप से देखना जो कि तत्त्वदर्शियों या योगियों को नैसर्गिक प्रज्ञा की ओर सङ्केत करता है। इस प्रकार दर्शन शब्द का अर्थ होता है तत्त्व का साक्षात्कार । न केवल वैदिक दर्शनों की परम्परा बौद्धों की परम्परा के अनुसार दार्शनिक तत्त्वों का निरूपण मानसिक तर्क की ऊहापोह नहीं होता, प्रत्युन महान् पुरुषों की नैसर्गिक प्रज्ञा या प्रतिभा पर आश्रित होना है, इस लिए दर्शन शब्द का प्रयोग (जिसका अर्थ है तत्त्वको साक्षात् रूप से देखना) मीमांसा दर्शन की अपेक्षा (जिसका शब्दार्थ है तर्क द्वारा परीक्षा) अधिक उपयुक्त समझा गया।

यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ के मुख्य विषय अर्थात् न्यायवैशेषिक शास्त्र के इतिहास और सिद्धान्तों का विशद निरूपण करने से पूर्व सभी दार्शनिक सम्प्रदायों के साहित्य और सिद्धान्तों का

ज्ञान/मीमांसा

25 साल से सत्ता के केंद्र में मोदी और हताश विपक्ष के सवाल

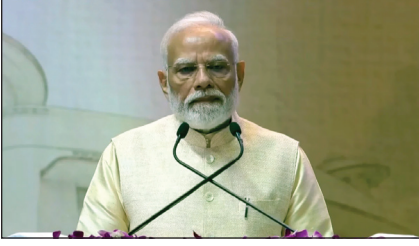
विनोद पाठक

7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज 25 साल बाद पीछे मुड़कर देखें तो यह सफर भारतीय राजनीति की सबसे असाधारण यात्राओं में दिखाई देता है। एक संगठन कार्यकर्ता से गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर। प्रधानमंत्री के रूप में भी मोदी 12 साल पूरे कर चुके हैं। इन 25 वर्षों में उन्होंने बहुत चुनाव जीते, बहुत विरोध झेले और कई बड़े फैसले लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लगातार राजनूतिक बहस के केंद्र में बने रहे। समर्थक हों या विरोधी, दोनों की राजनीति में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी साफ दिखाई देती है, लेकिन मोदी की कहानी को केवल उनकी उपलब्धियों और चुनावी जीत के जरिए समझना अधूरा होगा। उनकी राजनीति का दूसरा पक्ष भी है, वह पक्ष, जिसे विपक्ष लगातार सामने रखता रहा है।

विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि पिछले 12 वर्षों में सत्ता का बहुत ज्यादा केंद्रीकरण हुआ है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार और पार्टी के फैसलों में प्रधानमंत्री कार्यालय और खुद नरेंद्र मोदी की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा राजबूत हुई है। विपक्ष इसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय मानता है। विपक्षी दल यह भी कहते रहे हैं कि संसद में सरकार और विपक्ष के बीच संवाद कम हुआ है। महत्वपूर्ण विधेयकों को जल्दी पारित कराने, विपक्षी सांसदों के निलंबन और संसदीय बहस के समय को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

सरकार इन आरोपों को राजनीतिक आरोप बताती है और उसका तर्क है कि जनता ने उसे स्पष्ट जनादेश दिया है, लेकिन विपक्ष के लिए सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है। उसका कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना सरकार बनाने का अधिकार देता है, लेकिन विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यही टकराव आज चुनावी व्यवस्था के सवाल पर भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर सड़क पर उतर चुका है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव केवल मतदान का दिन नहीं है। मतदाता सूची से लेकर वोटों की गिनती तक पूरी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा होना चाहिए।

सरकार और चुनाव आयोग इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि चुनाव



प्रक्रिया नियमों और कानून के अनुसार चलती है, लेकिन विपक्ष का सवाल अपनी जगह है, अगर सब कुछ ठीक है तो इन सवालों का जवाब विस्तार से और पारदर्शी तरीके से क्यों न दिया जाए?

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति चुनावी जनादेश पर टिकी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ही जनता से मिलने वाला वोट है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों को हल्के में लेना किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। विपक्ष की दूसरी बड़ी शिकायत संस्थाओं को लेकर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की कार्रवाओं को लेकर विपक्ष कई बार सरकार पर निशाना साध चुका है।

सरकार का जवाब है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई राजनीति देखकर नहीं की जा सकती। सच यह है कि इन आरोपों और जवाबों के बीच जनता के मन में सवाल जरूर पैदा हुए हैं। लोकतंत्र में संस्थाओं की ताकत जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि उन पर पक्षपात का संदेह न हो। मोदी की राजनीति का एक और बड़ा मुद्दा सामाजिक और धार्मिक ध्ववीकरण है। भाजपा और मोदी के समर्थक इसे सांस्कृतिक आत्मविश्वास और लंबे समय से उपेक्षित भावनाओं की अभिव्यक्ति मानते हैं। विपक्ष का आरोप है कि धर्म और राष्ट्रवाद का राजनीतिक इस्तेमाल समाज में विभाजन बढ़ाता है। राम मंदिर से लेकर समान नागरिक संहिता, जनसंख्या और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों तक भाजपा ने अपनी विचारधारा को खुलकर राजनीति के केंद्र में रखा है। भाजपा के लिए यह उसके मूल विचारों की राजनीति है। विपक्ष के लिए चिंता यह है कि भारत जैसे विविध देश में सरकार को सभी समुदायों के बीच बराबरी और भरोसे की भावना बनाए रखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है।

आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र

अनन्या मिश्रा

आज ही के दिन यानी की 09 सितंबर को आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाने वाले महान साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म हुआ था। उन्होंने सिर्फ 34 साल की उम्र तक में इतना लिखा और इतना काम कर गए कि उनके समय को भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु ने गद्य, काव्य, नाटक, अनुवाद, निबंध और पत्रकारिता में उन्होंने जो लिखा-किया, वह कालजयी हुआ। आज हम सभी जो हिंदी बोलते और लिखते हैं, वह भारतेंदु की ही देन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है।

काशी के संपन्न वैश्य परिवार में 09 सितंबर 1850 को भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गोपालचंद्र था, जोकि एक अच्छे कवि थे। जब भारतेंदु

5 साल के थे तो उनकी मां का निधन हो गया और जब 10 वर्ष के हुए, तो पिता की मृत्यु हो गई। हरिश्चन्द्र काव्य-प्रतिभा अपने पिता से विरासत में मिली थी। भारतेंदु ने महज 5 साल की उम्र में अपने पिता को दोहा बनाकर सुनाया था। उन्होंने संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू भाषाएं भी सीख लीं।

बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला था। अंग्रेजी का चरित्र बढ रहा था और राजकाज और सभ्रांत वर्ग की भाषा फारसी थी। इस दौरान तक उर्दू भी चलन में आ गई थी। वहीं साहित्य में ब्रजभाषा का बोलबाला था। इस समय में भारतेंदु ने न सिर्फ खड़ी बोली का विकास किया, बल्कि साहित्य में नवीन आधुनिक चेतना का समावेश किया।



अविर्भाव हुआ था, उस समय देश गुलाम था और भारतीय लोगों में विदेशी सभ्यता के प्रति आकर्षण था। इस दौरान लोग अंग्रेजी पढ़ना और समझना गर्व की बात समझते थे। हिंदी के प्रति लोगों में आकर्षण काफी कम था, ऐसे में भारतेंदु ने अपनी लेखनी की धार को अंग्रेजी हुकूमत की ओर मोड़ दिया। वहीं लोगों में खुद की भाषा के प्रति भी आकर्षण पैदा करने का काम किया था।

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चन्द्र, श्री चंद्रावती, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषमस्य विषमौषधम्,

नरेंद्र मोदी दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे हैं। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। विपक्ष आंदोलन की भाषा में जनता से बात करना चाहता है। मोदी इस समय आस्था और अपने परिचित राजनीतिक प्रतीकों के जरिए अपने समर्थकों के बीच दिखाई दे रहे हैं। दोनों तस्वीरें लोकतंत्र की तस्वीरें हैं, लेकिन लोकतंत्र में सड़क पर उतरना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि जनता यह महसूस करे कि विरोध के पास कोई ठोस विकल्प भी है।

नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत शायद यही है कि उन्होंने अपने समर्थकों के बीच एक मजबूत भरोसा बनाया है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह उस भरोसे को अभी तक पूरी तरह तोड़ने वाली कोई दूसरी कहानी नहीं बना पाया है। इसका मतलब यह नहीं कि मोदी की राजनीति के सामने कोई चुनौती नहीं है। 25 साल की सत्ता अपने साथ थकान भी लाती है। लंबे समय तक एक ही नेतृत्व रहने पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। राजगार, महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दे आने वाले वर्षों में सरकार की परीक्षा लेते रहेंगे। इसके अलावा, वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव एक संकेत दे चुका है।

भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं कि मोदी की राजनीति खत्म हो गई, लेकिन यह जरूर बताता है कि मतदाता हमेशा एक ही तरीके से मतदान नहीं करता। गठबंधन की राजनीति की वापसी भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसलिए नरेंद्र मोदी की 25 साल की यात्रा को केवल विजय की कहानी मानना भी ठीक नहीं होगा। इसमें जीत है तो वापसी भी है, लोकप्रियता है तो विरोध भी है, मजबूत नेतृत्व है तो सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर चिंता भी है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।

मोदी के समर्थक उनकी उपलब्धियां गिनाएंगे। विपक्ष उनकी कमियां गिनाएगा। इतिहास दोनों को साथ रखकर फैसला करेगा, लेकिन आज की तारीख में एक बात साफ है, नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में हैं। उनके विरोधी लगातार चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके मुकाबले ऐसा विकल्प खड़ा नहीं कर पाए हैं, जो पूरे देश में उतना ही प्रभाव पैदा कर सके। शायद नरेंद्र मोदी को असली शक्ति यही है। उन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं जीते, उन्होंने भारतीय राजनीति का केंद्र अपने आसपास बना दिया।

चुनाव आयोग पर सवालों से विपक्ष को संजीवनी

राज कुमार सिन्हा

दिल्ली के जंतर-मंतर और मुंबई समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच कल सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त पद से हटाने और अंतरिम रूप से सस्पेंड करने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े कथित एकतरफा फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। सीजेआई का यह टिप्पणी, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर को दावा किया था कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए मद्ताओं का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के साथ जोड़े गए नए घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है।मामला इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और उसके आधार पर दाखिल याचिकाओं के बाद सामने आया, जिनमें दावा किया गया कि एसआईआर से जुड़े करीब 14 महत्वपूर्ण फैसलों पर दोनों चुनाव आयुक्तों ने आपत्तियां दर्ज की थी, जबकि फैसले भारत के निर्वाचन आयोग के नाम से आगे बढ़े थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले नहीं ले सकते हैं। दरअसल, फॉर्म-6 में बदलाव के जरिए जोड़े गए नए घोषणा-पत्र को लेकर राजनीतिक दलों का विरोध तब और बढ़ गया जब यह बात सामने आई कि निर्वाचन आयोग के अन्य निर्वाचन आयुक्तों की आपत्ति के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अकेले यह निर्णय लिया है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों ने यह कहते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी कि केंद्र सरकार द्वारा मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 में संशोधन किए बगैर फॉर्म-6 में बदलाव नहीं किए जा सकते हैं।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली



तीन सदस्यीय बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना ने ज्ञानेश कुमार को फिलहाल एक्स पार्टी सस्पेंड करने से इनकार किया है, लेकिन मामला खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल चुनाव आयोग और अदालत के बीच चल रही कानूनी प्रक्रिया तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। इसका सीधा संबंध देश की राजनीति, चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता और सत्तापक्ष तथा विपक्ष के बीच बढ़ते अविश्वास से भी है। यदि चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल लंबे समय तक बने रहते हैं, तो यह विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका सामान्य प्रशासनिक संस्था से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग के फैसलों पर राजनीतिक दलों और मतदाताओं का विश्वास चुनाव की निष्पक्षता की बुनियादी शर्त है। इसलिए जब आयोग के भीतर ही किसी निर्णय को लेकर मतभेद या असहमति की बात सामने आती है और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचता है, तो उसका राजनीतिक महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या बहुसदस्यीय चुनाव आयोग में किसी बड़े नीतिगत या चुनावी फैसले को मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले आगे बढ़ा सकते हैं?

यदि इस प्रश्न पर न्यायिक परीक्षण होता है और भविष्य में न्यायालय कोई स्पष्ट व्यवस्था देता है, तो इसका असर केवल मौजूदा विवाद पर नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की भविष्य की कार्यप्रणाली पर भी पड़ सकता है। इससे यह तय करने में मदद मिल सकती है कि आयोग के भीतर सामूहिक निर्णय प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संवैधानिक भूमिका का संतुलन किस प्रकार कायम किया जाना चाहिए। विपक्ष पिछले कुछ समय से चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची, ईवीएम, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर सवाल उठाता रहा है। एसआईआर का मुद्दा इस व्यापक राजनीतिक अभियान को एक नया आधार दे सकता है।

विशेष रूप से मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया का सवाल सीधे नागरिक के मतदान के अधिकार से जुड़ा है। यदि विपक्ष यह धारणा बनाने में सफल होता है कि किसी भी प्रक्रिया के कारण वास्तविक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से बाहर हो सकता है, तो यह मुद्दा चुनावी राजनीति में काफी प्रभावशाली हो सकता है। हालांकि विपक्ष के सामने चुनौती भी कम नहीं है। केवल आरोप लगाने से राजनीतिक विश्वसनीयता हासिल नहीं होगी। उसे यह साबित करना होगा कि किन क्षेत्रों में प्रक्रिते वास्तविक मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए, फ़ैसले में कहां गड़बड़ी हुई और उसके ठोस प्रमाण क्या हैं। यदि विपक्ष आंकड़ों और दस्तावेजों के साथ यह लड़ाई लड़ता है, तो उसका प्रभाव व्यापक हो सकता है।यह घटनाक्रम विपक्षी एकता के लिए भी एक साझा मुद्दा पैदा कर सकता है। अलग-अलग राय्यों में राजनीतिक रूप से एक-दूसरे के विरोधी दल भी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के सवाल पर एक मंच पर आ सकते हैं। विपक्ष के सामने तीन प्रमुख अवसर हैं,पहला, चुनाव आयोग की निष्पक्षता के सवाल को व्यापक लोकतांत्रिक मुद्दे में बदलना, दूसरा एसआईआर और

मतदाता सूची से जुड़े वास्तविक मामलों को दस्तावेजों और आंकड़ों के साथ जनता के सामने रखना, और तीसरा अलग-अलग विपक्षी दलों को एक साझा संस्थागत मुद्दे पर एकजुट करना। यदि विपक्ष इन तीनों मोर्चों पर सफल रहता है, तो यह विवाद आगामी चुनावों में उसके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी बन सकता है। खासकर उन राय्यों में जहां मतदाता सूची में बदलाव, नए मतदाताओं का पंजीकरण और पुराने मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर पहले से राजनीतिक संवेदनशीलता है। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना, संघीय ढांचे और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर विपक्ष की रणनीति कई बार राय्यों के राजनीतिक समीकरणों के कारण बिखर जाती है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाता सूची का प्रश्न ऐसा मुद्दा है जो लगभग हर विपक्षी दल के लिए समान राजनीतिक चिंता पैदा करता है। लेकिन विपक्ष की एकजुटता तभी टिकेगी जब वह इसे किसी एक व्यक्ति को हटाने की मांग तक सीमित न रखकर चुनावी संस्थाओं की स्वतंत्रता और पारदर्शिता का व्यापक प्रश्न बनाए। यदि अभियान केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ व्यक्तिगत राजनीतिक संघर्ष के रूप में दिखाई देता है, तो उसका प्रभाव सीमित हो सकता है। इसके विपरीत, यदि विपक्ष नियुक्ति प्रक्रिया, आयोग की जवाबदेही, निर्णय लेने की सामूहिक व्यवस्था, मतदाता सूची का पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी जैसे संस्थागत सुधारों को सामने रखता है, तो यह बहस कहीं अधिक गंभीर और प्रभावशाली हो सकती है। संभवतः इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा प्रभाव यही हो सकता है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बहस वास्तव में लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर बहस है। मतदाता सूची में एक योग्य नागरिक का नाम होना केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड का विषय नहीं है। यह उसके संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा हुआ है।

आज का इतिहास

- 1983 दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति चुन डू-ह्वान बर्मा के रंगून में एक हत्याकांड में बच गए।
- 1986 द फ़ैटम ऑफ़ द ओपेरा, म्यूज़िक द्वारा एंड्रयू लॉयड वेबरक्रिकेट द्वारा इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला ब्रॉडवे शो, लंदन के वेस्ट एंड में खोला गया।
- 1998 पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इस्लामी शरीयत कानून को देश के सर्वोच्च कानून के रूप में अनुमोदित किया।
- 2004 अफगानिस्तान ने अपना पहला लोकतांत्रिक चुनाव देश के पंजीकृत मतदाताओं के वोटिंग के 75 प्रतिशत अनुमान के साथ किया।
- 2005 साथ में, एंग्लिकन और कैथोलिक नेताओं ने इच्छामृत्यु के बारे में अपनी चिंताओं को सामने रखा है क्योंकि हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स विधायिका के लिए तर्क तैयार करता है।
- 2006 गूगल ने यू-ट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की।
- 2006 उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर आईसीटी का पहला परमाणु उत्पकरण परीक्षण किया।
- 2008 उत्तर कोरिया ने जहाजों को पीले सागर के एक क्षेत्र में नौकायन से प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि यह 10 छोटी दूरी की मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी करता है।
- 2009 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सेंटेरलाइट (एलसीआरओएसएस) को प्रक्षेपित किया।
- 2010 दो अन्य क्रांतिकारियों के साथ एक वरिष्ठ तालिबान कमांडर को नाटो और अफगान बलों के साथ मुर्गब जिले में गोलाबारी में मार दिया गया था।
- 2011 स्पेन के दक्षिण-पश्चिमी कैनरी द्वीपसमूह में एल हायरो के दक्षिणी तट पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप स्पष्ट रूप से बढ़ते मैग्मा के कारण हुआ था, जो एक लुप्त हो रहे ज्वालामुखी विस्फोट की आशंकाओं के कारण खाली किया गया था, जो 1793 में एल हिरो पर हुआ था।
- 2012 एथेंस में लगभग 25,000 लोग विरोध करते हैं क्योंकि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ग्रीस का दौरा करती हैं।
- 2012 पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफ़ज़ई को एक तालिबंगमन ने एक असफल हत्या के प्रयास में गोली मार दी थी।
- 2013 जूनो बृहस्पति की कक्षा में पृथ्वी पर उड़ता है, लेकिन फ्ल्टाई-बाय के दौरान एक गड़बड़ होता है जो इसे सुरक्षित मोड में रखता है।
- 2014 अमेरिकी शेयर बाजार तेजी से घटता है, एस एंड पी 500 और डब्लू जेम्स इंडस्ट्रियल एवरेज में लगभग 2 प्रतिशत की कमी आती है।

उत्तराखंड कांग्रेस में छिड़ी महाभारत बड़े सियासी तूफान के संकेत दे रहे हैं

नीरज कुमार दुबे

पहाड़ की राजनीति में वैसे तो मौसम कब करवट ले ले, कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार कांग्रेस के भीतर का मौसम कुछ ज्यादा ही विगड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भाजपा लगातार संगठन को चुनावी मोड़ में ले जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही घर की उठापटक से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही है। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बार फिर वही पुराने चेहरे हरीश रावत हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सवाल यह है कि लगातार चुनावी पराजयों के बाद भी कांग्रेस आखिर बार–बार उन्हीं पर दांव क्यों लगाये ? और क्या अब भी उनके पास उत्तराखंड की राजनीति को निर्णायक रूप से प्रभावित करने की उतनी ही ताकत बची है ?

हम आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत की ‘धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा’ को लेकर साफ संदेश दिया है कि चुनावी राज्य में किसी एक नेता का समानांतर अभियान नहीं चल सकता और पार्टी को सामूहिक रूप से चुनाव लड़ना होगा। लेकिन हरीश रावत पीछे हटने की बजाय अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। उनका कहना है कि वे कांग्रेस को नहीं सत्ता में वापस लाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। सुनने में यह बात बिल्कुल कांग्रेस के हित में लगती है, लेकिन राजनीति में सिर्फ इरादा नहीं, नतीजे भी देखे जाते हैं और यहीं से हरीश रावत की मौजूदा राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठने शुरू होते हैं।

हरीश रावत उत्तराखंड के बड़े नेताओं में रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, केंद्र को राजनीति में लंबी पारी खेली और उत्तराखंड कांग्रेस को कई मुश्किल दौर में संभाला। लेकिन राजनीति में किसी नेता का कद सिर्फ उसके पुराने पदों से नहीं मापा जाता। चुनावी राजनीति में जनता का फैसला सबसे बड़ा पैमाना होता है और अगर इसी पैमाने पर हरीश रावत के पिछले कुछ चुनावों को देखा जाए तो तस्वीर बहुत चमकदार नहीं दिखाई देती।

2017 का विधानसभा चुनाव शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत ने दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया। हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा, दोनों सीटों पर वह मैदान

में उतरे, लेकिन दोनों जगह हार गए। हरिद्वार ग्रामीण में भाजपा के यतीश्वरानंद ने उन्हें 12 हजार से ज्यादा वोटों से हराया, जबकि किच्छा में भाजपा के राजेश शुक्ला ने उन्हें शिकस्त दी। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा उत्तराखंड का सबसे बड़ा कांग्रेसी चेहरा विधानसभा तक नहीं पहुंच सका। उस चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खराब हुई कि पार्टी 70 में से सिर्फ 11 सीटों पर सिमट गई और भाजपा ने 57 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा कर लिया।

वैसे राजनीति में हार के बाद वापसी संभव होती है और हरीश रावत ने भी कोशिश जारी रखी। 2019 में वे नैनीताल–ऊधमसिंह नगर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन भाजपा के अजय भट्ट के सामने टिक नहीं सके। अजय भट्ट को 7.72 लाख से ज्यादा वोट मिले और हरीश रावत करीब 4.33 लाख वोट पर रुक गए। हार का अंतर तीन लाख से ज्यादा रहा। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव आया तो रावत ने लालकुआं को अपना रणक्षेत्र बनाया। इस बार भी भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट ने उन्हें 17,527 वोटों के अंतर से हरा दिया। यानी 2017 में दो विधानसभा सीटों पर हार, 2019 में लोकसभा की हार और 2022 में विधानसभा की हार, लगातार चुनावी पराजय का यह सिलसिला किसी भी नेता के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा करने के लिए काफी है।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से कांग्रेस ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा। मुकाबला भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से था। नतीजा फिर कांग्रेस के खिलाफ गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीरेंद्र रावत को करीब 1.64 लाख वोटों से हरा दिया। यानी जिस परिवार को कांग्रेस लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति में एक मजबूत आधार मानती रही है, उसके सामने भी चुनावी जमीन उतनी मजबूत दिखाई नहीं दी, जितनी पार्टी शायद मानती रही है।

यहीं से सवाल पैदा होता है कि बार–बार हरीश रावत पर ही दांव क्यों लगाया जाये ? क्या कांग्रेस के पास उत्तराखंड में कोई नया चेहरा नहीं है ? क्या पार्टी ने नई पीढ़ी का नेतृत्व तैयार नहीं किया ? क्या संगठन के भीतर ऐसा कोई नेता नहीं है जो हरीश रावत के बिना कांग्रेस

विचार



को चुनावी मुकाबले में खड़ा कर सके ? या फिर कांग्रेस हाईकमान को अब भी लगता है कि चुनाव जीतने की क्षमता भले कम हुई हो, लेकिन हरीश रावत के पास वह राजनीतिक अनुभव, जनसंपर्क और संगठनात्मक पकड़ है जिसे नजरअंदाज करना पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा ?

देखा जाये तो हरीश रावत की सबसे बड़ी ताकत यहीं है कि वे उत्तराखंड की राजनीति को बेहद करीब से जानते हैं। वे पहाड़ की भाषा समझते हैं, मैदान की राजनीति को समझते हैं और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ भी है। वे राजनीतिक मुद्दों को जनता की भाषा में बदलने की कला जानते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी अब सामने है। उनकी व्यक्तिगत चुनावी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब कोई नेता खुद लगातार चुनाव हार रहा हो तो उसके समर्थकों के लिए यह कहना आसान नहीं होता कि वही नेता पार्टी को सत्ता तक पहुंचा देगा।

यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर हरीश रावत की भूमिका को लेकर असमंजस दिखाई देता है। पार्टी उन्हें पूरी तरह किनारे नहीं कर सकती, क्योंकि उनका अनुभव और जनाधार अब भी उपयोगी है। लेकिन पार्टी उन्हें पूरी तरह आगे भी नहीं कर सकती, क्योंकि तब बाकी नेताओं और गुटों के बीच असंतोष बढ़ने का खतरा है। अगर हरीश रावत अपनी अलग राजनीतिक गतिविधियां जारी रखते हैं तो हाईकमान को डर है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस का मंच अलग–अलग हिस्सों में बंट जाएगा।

देखा जाये तो उत्तराखंड कांग्रेस की असली समस्या यही है। उसके पास नेता बहुत हैं, लेकिन नेतृत्व का सर्वमान्य चेहरा नहीं है। हर नेता अपने समर्थकों के साथ खड़ा है, हर गुट अपनी राजनीतिक जगह चाहता है और

दिल्ली चाहती है कि चुनाव आते–आते सभी एक मंच पर दिखाई दें। लेकिन पहाड़ की राजनीति में जितनी ऊंचाई होती है, उतने ही मोड़ भी होते हैं। कांग्रेस के सामने इस समय सबसे बड़ा मोड़ नेतृत्व का ही है।

उधर भाजपा की कहानी बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। 2017 में भाजपा ने 70 में से 57 सीटें जीतकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। 2022 में भाजपा का आंकड़ा घटकर 47 जरूर हुआ, लेकिन सत्ता उसके हाथ से नहीं निकली। कांग्रेस 19 सीटों तक पहुंची, लेकिन सरकार बनाने से काफी दूर रही। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तराखंड की पांचों सीटें जीतकर कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलने दिया। यानी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के पास लगातार चुनावी जीत की मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है और मजबूत संगठन की ताकत भी।

भाजपा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह पिछली जीत के भरोसे बैठी दिखाई नहीं देती। वह उन सीटों पर भी संगठन मजबूत करने में जुटी है जहां उसे विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। पार्टी की तैयारी बूध स्तर तक दिखाई देती है और उसके सामने चुनाव सिर्फ सरकार बचाने का नहीं, बल्कि उत्तराखंड में अपने राजनीतिक वर्चस्व को और मजबूत करने का है।

इसके उलट कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ मुद्दों की कोई कमी नहीं है। बेरोजगारी है, भर्ती परीक्षाओं के सवाल हैं, पलायन है, पहाड़ के गांवों का खाली होना है, जमीन और जंगल के सवाल हैं, युवाओं की नाराजगी है और स्थानीय अस्मिता से जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों को एक बड़े राजनीतिक अभियान में बदलने से पहले कांग्रेस को अपने भीतर की लड़ाई खत्म करनी होगी। यही वह जगह है जहां भाजपा को सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है।

हालांकि कांग्रेस के लिए उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। 2024 में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव जीतना यह दिखाता है कि भाजपा अजेय नहीं है। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस के सामने चुनौती छोटी नहीं है। उसे सिर्फ भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने से काम नहीं चलेगा, उसे अपना संगठन, अपना नेतृत्व और अपना चुनावी संदेश तीनों मजबूत करने होंगे।

इसी मोड़ पर हरीश रावत का सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर रावत पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता के बीच जाना चाहते हैं तो कांग्रेस को उनके अनुभव का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी सक्रियता कांग्रेस के भीतर एक और भूवीकरण पैदा करती है तो वही सक्रियता पार्टी के लिए बोझ बन सकती है। कांग्रेस को यह तय करना होगा कि हरीश रावत उसके लिए एक वरिष्ठ मार्गदर्शक और स्टार प्रचारक हैं या फिर एक बार फिर पूरा चुनाव उन्हीं के इर्द–गिर्द लड़ा जाएगा। क्योंकि इन दोनों रास्तों में जमीन–आसमान का फर्क है।

देखा जाये तो उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत का अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि उनका सबसे मजबूत दौर पीछे छूट चुका है। उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता अब सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि वे कितनी बड़ी रैलियां करते हैं या कितने जिलों में यात्रा निकालते हैं। असली सवाल यह होगा कि क्या वे कांग्रेस के भीतर बिखरे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर ला सकते हैं और क्या उनकी मौजूदगी पार्टी के वोट में बदल सकती है ?

वहीं कांग्रेस को भी यह समझना होगा कि उत्तराखंड की जनता सिर्फ पुराने चेहरों की यादों पर वोट नहीं करती। पहाड़ की जनता अपने नेताओं से हिसाब मांगती है। वह पूछती है कि पांच साल में क्या हुआ, रोजगार कहां है, गांव क्यों खाली हो रहे हैं, सड़क और स्वास्थ्य की हालत क्या है और आने वाली पीढ़ी के लिए राज्य में क्या बचा है। इसलिए 2027 का चुनाव अगर कांग्रेस सिर्फ हरीश रावत बनाम भाजपा बनाकर लड़ती है तो यह उसकी रणनीतिक भूल होगी। उसे हरीश रावत के अनुभव को इस्तेमाल करते हुए एक नई राजनीतिक टीम और नया नेतृत्व सामने लाना होगा। वरना खतरा यह है कि कांग्रेस हर बार पुराने चेहरे को देखकर पहाड़ की चढ़ाई शुरू तो कर दे, लेकिन चुनाव की चोटी तक पहुंचने से पहले ही फिर किसी पुराने मोड़ पर लौट आए। क्योंकि सवाल सामने पक्ष और विपक्ष के सियासी वजूद का नहीं है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस अपने पुराने सियासी चेहरे से आगे निकलकर नया नेतृत्व पैदा कर पाएगी, या फिर 2027 में भी पहाड़ वही पुराना सवाल पूछेगा कि कांग्रेस के पास आखिर नया क्या है ?

पाकिस्तान में सड़कों पर लोकतंत्र का संघर्ष?

राजेश बादल

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को डर सता रहा है कि अगर मुल्क में प्रतिपक्ष के प्रदर्शन इस तरह होते रहे तो अंतरराष्ट्रीय छवि पर खराब असर पड़ेगा। वे इसलिए भी आंदोलन की सामिति चाहते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। उनकी यह सोच चौकाती है। शहबाज शरीफ को छवि और वित्तीय हालत की चिंता तो है, लेकिन वे उसके कारणों की जड़ में नहीं जाना चाहते। वे ऐसे तथ्याकथित लोकतंत्र के समर्थक दिखाई देते हैं, जिसमें विपक्ष को न तो सम्मान दिया जाता है और न ही उसके अधिकार दिए जाते हैं। ऐसे में जम्हूरियत का जो नाटक चल रहा है, वह लंगड़े लोकतंत्र का मुजाहिदा करता है। विश्व विरादरी को फैसला किया है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र मजाक बनकर रह गया है। ऐसे मसखरे लोकतंत्र से कोई भी देश कैसे कारोबारी रिश्ते रख सकता है और वहां अर्थव्यवस्था संभालने में सहायता कर सकता है? अफसोस! शहबाज शरीफ यह हकीकत समझने के लिए तैयार नहीं हैं। विडंबना यह है कि वे सबसे बड़े विपक्षी नेता इमरान खान नियाजी को गैरकानूनी ढंग से जेल में अंततकाल तक रक़्द करने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। वे भूल जाते हैं कि जिस सर्वशक्तिमान सेना के आगे वे नतमस्तक हैं, वह उनके सगे बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा कर चुकी है। क्या उन्हें गारंटी मिली है कि उनके साथ फौज कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी? लेकिन यह उस देश की विडंबना है कि हर प्रधानमंत्री को पता होता है कि सेना उसकी क्या दुर्गति करेगी, फिर भी वह फौज के इशारों पर कटपुतली की तरह नाचता है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चार

मार्च से अपने नेता की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद के लिए शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं। दिलचस्प यह है कि इसका नेतृत्व खैबर पख्तूनख्वा प्रदेश के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी कर रहे हैं। अर्थात एक प्रदेश की सरकार अपनी ही केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाल रही है। दोनों सरकारों को अपनी-अपनी नौकरशाही और पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। अब सिर्फ सेना है, जो केंद्र सरकार के बचाव में सड़कों पर उतर सकती है क्योंकि प्रादेशिक सुरक्षाबल तो ऐसा करने से रहे। कहा जा सकता है कि जो सेना अपने प्रधानमंत्री को बचा सकती है, वह उनके बड़े हुए दिन भी तय कर सकती है। शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान के दल से बातचीत नाकाम होने दी और चर्चा विफल हो जाने दी। सरकार जानती है कि यदि इमरान की पार्टी से समझौता हुआ तो उसे पूर्व प्रधानमंत्री को रिहा करना ही पड़ेगा। अभी शेर पिंजरे में बंद है तो कम खतरनाक है। वह अशर्कित है कि यदि उसने इमरान का पिंजरा खोल दिया तो वह भूखा शेर किसे निगलेगा – कोई नहीं जानता। जाहिर है, शहबाज शरीफ भयभीत हैं। पाकिस्तानी फौज केवल अपने प्रति वफादार होती है। यदि उसने देखा कि इमरान खान के पीछे मुल्क की अवाम पागल है तो वह येन केन प्रकारेण इमरान खान को फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ले आएगी और तब शहबाज शरीफ की जगह शायद रावलपिंडी की उसी जेल में होगी, जहां अभी इमरान खान बंद हैं। इसलिए वे प्रतिपक्ष के आंदोलन को कुचलने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्षी जुलूस अब राजधानी इस्लामाबाद से केवल डेड सी कीलोमीटर दूर रह गया है। यही रफ्तार रही तो गुस्वार की दोपहर तक सारे आंदोलनकारी इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे।

सनत जैन

लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है, राजतंत्र में सत्ता राजा की होती है जबकि लोकतंत्र में सत्ता जनता की होती है। राजा तक पहुंचने के लिए अनुमति आवश्यक हो सकती थी, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि किसी अधिकारी, प्रशासनिक प्रमुख अथवा संवैधानिक संस्था के प्रमुख की समस्या रखने के लिए अनुमति मिलने तक दरवाजे पर खड़ा रहे, मिलने के लिए अनुमति मांगे, यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। जनप्रतिनिधि जनता के मत से निर्वाचित होकर संसद या विधायसभा या नगरी निकायों तक पहुंचता है। उसका दायित्व केवल सदन में बैठना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार, प्रशासन तथा संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंचाना भी है। इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधि, शासन–प्रशासन के बीच संवाद लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। सामान्य लोकतांत्रिक परंपरा यही रही है, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी अथवा संवैधानिक पदाधिकारी से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं, यदि संबंधित अधिकारी उस समय उपलब्ध नहीं होता है, तो सुविधा के अनुसार सम्मानपूर्वक जनप्रतिनिधि से समय तय करता है। जनप्रतिनिधि को मिलने से पहले अनुमति लेना या मिल सकता है, या नहीं, यह व्यवस्था लोकतांत्रिक संवाद को



नौकरशाही की अनुमति पर निर्भर बना सकती है। ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाल ही में लगभग 300 सांसदों द्वारा चुनाव आयोग से मिलने की कोशिश के प्रसंग ने इसी प्रश्न को जन्म दिया है। यदि इतने सांसद एक साथ किसी संवैधानिक संस्था तक पहुंच रहे थे, पूर्व सूचना होने के बाद भी उनके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, चुनाव आयोग के कार्यालय में प्रतिनिधि मंडल से मिलना संभव नहीं था, ऐसी स्थिति में क्या बाहर से ज्ञापन नहीं लिया जा सकता था? क्या आयोग का कोई अधिकारी उनसे मिलकर उनकी बात नहीं सुन सकता था? लोकतंत्र में असहमति और शिकायत को सुनना कमजोरी नहीं, बल्कि संस्थाओं की मजबूती और लोकतांत्रिक व्यवस्था का जीता-जागता प्रमाण है।

इससे भी बड़ा प्रश्न यह है, सांसदों को संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाने से पुलिस रोकती है। तो ऐसी कार्रवाई किसके आदेश पर हुई? दिक्षी पुलिस ने यह कार्रवाई क्यों की? जनप्रतिनिधियों को जाने से रोकना, किस

अधिकार के तहत किया गया? किस लोकतांत्रिक आवश्यकता या किस कानून के तहत रोका गया? जनप्रतिनिधियों को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था का तर्क दिया जा सकता है, लेकिन यह शांतिपूर्ण पैदल मार्च था। जितनी कानून

व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की थी वहीं जिम्मेदारी इन सांसदों की भी थी। फिर भी उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया। स्पष्ट रूप से यह कृत्य सांसदों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने जैसा है। समस्या केवल एक घटना या किसी एक संस्था की नहीं है। संसद और विधानसभाओं में जन प्रतिनिधियों को बोलने के लिए समय, नियम और प्रक्रियाओं की दीवारों से गुजरना पड़ता है। बोलने के पहले ही उनसे ऑर्थेंटिकेशन मांगा जाता है। नियम आवश्यक हैं, क्योंकि सदन अनुशासन से चलता है। नियमों का उद्देश्य जन प्रतिनिधियों की आवाज को दबाना नहीं, बल्कि हर पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर देना होना चाहिए। जनता का चुनाव हुआ प्रतिनिधि जब अपनी बात अपने ही सदन में नहीं रख पाएगा, तो फिर लोकतंत्र में जनता की आवाज कहां सुनी जाएगी?

इसी प्रकार प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही लोकतंत्र का मूल तत्व है। सांसद या विधायक किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनता की समस्या को लेकर

अधिकारी के पास जाता है। यदि उसे लगातार जवाब न मिले, मुलाक़ात न हो, ज्ञापन स्वीकार न किया जाए और समस्याएं लंबित रहें, तो धीरे–धीरे जनता का विश्वास शासन–प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं से उठने लगता है। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है, जनता की सत्ता, शासन एवं प्रशासन में भागीदारी, निर्वाचित प्रतिनिधियों की गरिमा, संस्थाओं की स्वतंत्रता, प्रशासन की जवाबदेही और सभी पक्षों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जनप्रतिनिधि का सम्मान व्यक्ति का नहीं बल्कि उस जनता का सम्मान है, जिस मतदाताओं के समूह ने उसे चुना है। वर्तमान स्थिति में संसद, विधानसभा, प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं के बीच संवाद की जगह टकराव बढ़ रहा है। लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बंट रहा है। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। संस्थाएं जब संवाद के दरवाजे बंद करती हैं, तो असंतोष सड़क पर आता है। जब संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास कमजोर होता या टूटता है, ऐसी स्थिति में भीड़तंत्र मजबूत होने लगता है। भीड़ स्वयं न्याय करने के लिए सड़क पर निकल पड़ती है। भीड़ के पास संख्या और शक्ति हो सकती है, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। लोकतंत्र को बनाए रखने की पहली शर्त है, जन प्रतिनिधियों को बोलने दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए।

एसआईआर पर हंगामा, हकीकत से ज्यादा फसाना

अ्देश चतुर्वेदी

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। विशेषकर विपक्षी दल जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, उससे माहौल में एक भ्रम फैल रहा है। विपक्षी हंगामे और सवालों के चलते ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है, जो मानने लगे हैं कि मतदाता सूची की जांच एक तरह से नागरिकता की जांच हो गई है। लोग एक बरागी वोटर न होने को बर्दाश्त कर भी लें, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि उसकी जन्मजात नागरिकता पर सवाल उठे या वह खतरे में पड़े। कहना न होगा कि विशेषकर पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर के बहाने विपक्ष यह भ्रम और डर–दोनों फैलाने में किंचित सफल रहा है। हालांकि यह भी सच है कि ऐसा भ्रम और डर सिर्फ पश्चिम बंगाल और बिहार के ही कुछ इलाकों में ही दिख रहा है। एसआईआर उत्तर प्रदेश में भी हुआ है और दिल्ली में भी जारी है। एसआईआर तमिलनाडु में भी हुआ है। लेकिन यहां के मतदाताओं के बीच ऐसा भ्रम और डर न के बराबर दिखा है।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार और पश्चिम बंगाल में ऐसा डर क्यों दिख रहा है? इसकी वजह है, वहां पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश से बड़ी घुसपैठ। पश्चिम बंगाल में जब सत्ता में वाममोर्चा था, तब यही ममता बनर्जी वहां घुसपैठ के मुद्दे को उछालती रहती थीं और वाममोर्चे पर आरोप लगाती रहती थीं कि वह इसे बढ़ावा दे रहा है। ममता बनर्जी इस बहाने परोक्ष रूप से वाममोर्चा पर आरोप लगाती थीं कि मतदाता बने घुसपैठियों के ही सहारे वह पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज है। बाद के दिनों में ये मतदाता ममता के समर्थक हो गए और ममता की सत्ता के आधार बनने लगे तो उन्हें भी यह मामला फिजूल का लगने लगा। बिहार का सीमांचल इलाका भी बांग्लादेशी घुसपैठ से प्रभावित रहा है। इसलिए वहां भी ऐसे



सवाल और भ्रम उठ रहे हैं। चूंकि एसआईआर में ऐसे अवैध मतदाता ज्यादा सवालों के घेरे में हैं या फिर उनके नाम कट रहे हैं, इस वजह से इन्हीं राज्यों में यह मुद्दा कुछ ज्यादा तुरश दिख रहा है।

मतदाता सूची में सुधार और उसमें चुनाव आयोग एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठे हैं। सवाल यह भी है कि क्या एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे सवाल असल में प्रक्रियात्मक और कानूनी हैं या इनके जरिए सिर्फ राजनीति हो रही है? पहले ही कहा जा चुका है कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों की सबसे ज्यादा आपत्तियां बिहार और पश्चिम बंगाल से जुड़ी बताई जा रही हैं। कुछ राजनेताओं और दलों ने एसआईआर के आधार पर इन राज्यों के चुनावी परिणामों और मतदाता सूची की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। यहां ध्यान रखने की बात है कि एसआईआर केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी हुआ, लेकिन वहां बिहार या पश्चिम बंगाल की तरह इस पर सियासी विवाद नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यदि कुछ राज्यों में एसआईआर को लेकर गंभीर आपत्ति नहीं है तो फिर एक या दो राज्यों में गंभीर आपत्तियां क्या राजनीतिक एजेंडे की वजह से तो नहीं उठाई जा रहीं? एसआईआर को देखने और समझने की एक ही कसौटी हर राज्य में क्यों नहीं लागू की जा रही है? इससे तो यही संकेत जाता है कि इसका

सियासी विरोध सेलेक्टिव है और दोहरे मापदंड से भरा हुआ है।

एसआईआर को लेकर जारी मौजूदा बहस में नागरिकों के लिए कुछ प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ● क्या पुनरीक्षण निर्धारित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ ? ● क्या किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया ? ● यदि ऐसा हुआ, तो क्या दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए उसे सुधारा गया ? ● क्या अलग–अलग राज्यों में समान प्रक्रियाओं को समान कसौटी पर देखा जा रहा है ?

एसआईआर, निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक तो है, लेकिन आरोप और प्रमाण, ड्राफ्ट सूची और अंतिम सूची, याचिका और न्यायिक आदेश तथा राजनीतिक मांग और कानूनी कार्रवाई, के बीच समझदारी से अंतर बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अच्चल तो मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बहस तथ्यों, कानून और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग बार–बार यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि एसआईआर मतदाताओं को बेहतर सुविधा देने की व्यवस्था है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है, कोई भी वैध और योग्य मतदाता छूटे नहीं। मोटे तौर पर एसआईआर का एक ही मकसद है, हर योग्य और वैध मतदाता को सूची में जोड़ना, दिए गए पते पर न रहे मतदाताओं और मतकों का नाम सूची से हटाना। इसके साथ ही विदेशी और घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करना है। एक आरोप यह लग रहा है कि मतदाता सूची तैयार करने में ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर की भूमिका बीएलओ और ईआओ की तुलना में बढ़ गई है, जिसकी वजह से मतदाता सूची को फाइनल करने के ईआओ के अधिकार दरकिनार हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।

नाना पाटेकर: अभिनय का बागी, जो जिंदगी में भी किरदार निभाता रहा

जयसिंह रावत

भारतीय सिनेमा में कुछ कलाकार अपनी खूबसूरती से पहचाने जाते हैं, कुछ लोकप्रियता से और कुछ अभिनय क्षमता से। लेकिन नाना पाटेकर ऐसे अभिनेता थे, जिनकी पहचान किसी एक विशेषता में समेटना कठिन है। उनके चेहरे पर सामान्य भारतीय की बेचैनी, आवाज में व्यवस्था के प्रति आक्रोश, आंखों में संघर्षों की छाया और अभिनय में ऐसी स्वाभाविकता थी कि दर्शक अक्सर अभिनेता और उसके किरदार के बीच अंतर भूल जाता था। वह न परंपरागत नायक थे, न फिल्मी दुनिया की चमक-दमक में सहजता से समाने वाले सितारे। उन्होंने अपना रास्ता बनाया और अपनी शर्तों पर चलते रहे। आठ अक्टूबर 2026 को उनके निधन के साथ भारतीय सिनेमा का एक ऐसा स्वर खामोश हो गया, जिसने अभिनय को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज की विसंगतियों और मानवीय संवेदनाओं की महारथ्यिक बनाया था। एक जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में जन्मे नाना पाटेकर का वास्तविक नाम विश्वनाथ पाटेकर था। पारिवारिक कारोबार में आई कठिनाइयों ने उन्हें कम उम्र में जीवन की कठोर वास्तविकताओं से परिचित कराया। उनका अभिनय किसी सुविधमसंपन्न जीवन की कल्पनाओं से नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य के अनुभवों से उज्जा प्रतीत होता था। उनके किरदारों में मजदूर की थकान, किसान की विवशता, व्यवस्था से निराश नागरिक का गुस्सा और अस्तित्व के लिए संघर्ष करते मनुष्य की बेचैनी दिखाई देती थी। वर्ष 1978

की फिल्म गमन से हिंदी सिनेमा में उनकी उपस्थिति दर्ज हुई, लेकिन पहचान बनाने में समय लगा। उस दौर में सुंदर चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व, रोमांस और नृत्य लोकप्रिय नायक की प्रमुख शर्तें थीं। नाना ने इन स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने साबित किया कि अभिनय की असली ताकत चेहरे की बनावट नहीं, चरित्र की विश्वसनीयता होती है। वर्ष 1989 की फिल्म परिंदे ने नाना पाटेकर को नई ऊंचाई दी। उनके परिंदेगा अन्ना के चरित्र ने हिंदी सिनेमा के खलनायकों की परंपरागत छवि बदल दी। यह अपराधी केवल क्रूर नहीं था, बल्कि भय, असुरक्षा और मानसिक विचलन से भी ग्रस्त था। नाना ने दिखाया कि खलनायक की भयावहता केवल शारीरिक शक्ति या ऊंची आवाज में नहीं, उसकी मानसिक जटिलताओं में भी छिपी होती है। इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर सम्मान मिला। इसके बाद अंगार, तिरंगा, क्रांतिवीर, अग्निसाथी, यशवंत, अब तक छप्पन और अपहरण जैसी फिल्मों ने उनकी पहचान को विस्तार दिया। वह कभी विद्रोही नागरिक बने, कभी कठोर पुलिस अधिकारी, कभी अपराध की दुनिया का भयावह चेहरा और कभी पारिवारिक संबंधों में उलझा व्यक्ति (विशेष रूप से 1994 की क्रांतिवीर में प्रताप का उनका किरदार दर्शकों की स्मृति में स्थायी स्थान बना गया। उसमें साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक पाखंड और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध सामान्य नागरिक की छटपटाहट सुनाई देती थी। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।



सुनहरी आभा का जैसलमेर

राजस्थान के पश्चिमी छोर पर थार मरुस्थल में बसे इस खूबसूरत शहर के किले, प्राचीन मंदिरों और रेत पर उंट की सवारी का लुत्फ लेने के लिए अब तमाम साधन उपलब्ध हैं। देश के सबसे गर्म शहरों में शुमार जैसलमेर को रेतीली जमीन पर बसा होने के कारण पहले मेरू नाम से जाना जाता था। सन 1156 में जैसलमेर की स्थापना भाटी राजा जैसल ने की थी और 12 साल तक यहां शासन किया।



लुभाने लगे तालाब और स्तूप

मध्य प्रदेश के प्राचीन धरोहरों की तरफ पूरी दुनिया के पर्यटक मानो खिंचे चले आ रहे हैं। बिहार के बौद्ध सर्किट की तरह ही मध्य प्रदेश भी विश्व पर्यटन पर अपना अमिट अक्स छोड़ने लगा है। भोपाल की गैस त्रासदी दिल दहलाने वाली जरूर है लेकिन इस शहर का एक दूसरा रूप भी है जो मन और आंखों को मोहने वाला है। तालाबों के शहर भोपाल की गंगा जमुनी संस्कृति आधुनिकता का आवरण पहने सैलानियों के मन प्राण पर छा रही है। भोपाल ही नहीं खजुराहो और मांडू जैसे पर्यटन क्षेत्र भी पर्यटकों के जमघट के गवाह बन रहे हैं। प्राचीन धरोहरों से समृद्ध यह प्रदेश आधुनिकता के हाईवे पर भी किसी से पीछे नहीं है। राजधानी भोपाल को नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल जैसे आधुनिक रूपों ने भी सजाया है। अरेरा और शामला हिल्स स्थित रेस्तरां, म्यूजियम और होटल सैलानियों के लिए खासे चर्चित हो रहे हैं। %भोपाल ब्यूटी% के नाम से चर्चित ऊपरी तालाब में स्पीडबोटों में आनंद की अटखैलियों में डूबते-उतारते धनी लोग एक अनोखा दृश्य उपस्थित करते हैं। तालाबों के उत्तर में पुराना शहर है। भोपाल से 46 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में गोलाई लिए एक पहाड़ी का अभ्युदय हुआ है, जिसे सांची के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी पर भारत के कुछ अति प्राचीन बौद्ध स्थल बने हुए हैं। सांची का बौद्ध स्तूप अपनी गरिमा और ऐतिहासिकता के साथ मध्य प्रदेश की गरिमा में चार चांद लगा रहा है। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने स्तूप बनाने के लिए अपनी पत्नी के जन्म स्थान के पास इस जगह को चुना।बुजों से सजा यह स्थल धार्मिक अवशेषों का संग्रह करने के लिए बनाया गया था। इस इलाके में यह पहला बौद्ध स्मारक है। अल सुबह और शाम इन स्तूपों की छटा में जो निखर आता है, उसे देख कर ही महसूस किया जा सकता है। सांची के आसपास सोनारी, सतधारा, अंधेर, गिरासपुर जैसे बौद्ध स्थल बिखरे पड़े हैं। सांची से 10 किलोमीटर उत्तर-पूर्व वेतवा और बेस नदियों से सिंचित विदिशा ईशा पूर्व 5वीं और 6ठी शताब्दी में वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र था। विदिशा भी पर्यटकों के लिए प्राचीन धरोहरों का एक अप्रतिम स्थल साबित होता है। इस सरजमीं के इतिहास को सम्राट अशोक, सिंधिया और मुगलों के आगमन ने समृद्ध किया है। खजानों के देवता कुबेर यक्ष की पत्थर की तीन मीटर ऊंची प्राचीन मूर्ति पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र बन रही है। वहीं के अन्य प्राचीन आकर्षणों में प्रेम आलिंगन में बद्ध 11वीं सदी में ढली साँप दर्पति, हनुमान एवं प्रेम के देवता कामदेव की मूर्तियाँ शामिल हैं। खजुराहो मंदिर यूनेस्को की विश्व-विरासत की सूची में शामिल है। विश्व पर्यटन के मानचित्र में खजुराहो का नाम प्रमुखता से उभर रहा है। खजुराहो कामशास्त्र पर आधारित मूर्तियों का समूह है। यह परिसर चंदेल वंश के राजाओं के समय 950 ई. से 1050 ई. के बीच बना था, जिसमें 85 मंदिर थे, हालाँकि अब सिर्फ 22 मंदिर ही बचे हैं। इनके अलावा यहाँ सिर्फ कंदरिया महादेव का मंदिर ही बचा है। यह मंदिर पाँच मुख्य वर्गों में विभाजित है, जिनमें तीन वर्ग छोटे मंदिरों के हैं। मंडप में प्रवेश करने पर सभाकक्ष पड़ता है, फिर एक गलियारा पार करने पर मंदिर का गर्भगृह मिलता है, जहाँ प्रतिमा स्थापित है। ऊँचे चबूतरे पर स्थित इन मंदिरों में कुछ बड़े, कुछ छोटे मंदिर हैं।



आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा

भारत में प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में सबसे प्रथम स्थल है आनंदपुर साहिब का गुरुद्वारा। सिख धर्म के लोग में यह गुरुद्वारा जागृत है। मान्यता है कि इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने वाले श्रद्धालुओं की मुराद पूरी होती है। यह गुरुद्वारा पंजाब के उत्तर-दक्षिण क्षेत्र में चंडीगढ़ से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सन् 1664 में श्री गुरु तेग बहादुर ने माकहोवाल के प्राचीन क्षेत्र में आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा बनवाया था। गुरु गोबिंद सिंह ने इस स्थल पर 25 साल आनंदपुर में व्यतीत किया है। सन् 1936 -1944 में तख्त केसरगढ़ साहिब बनाया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि तख्त साहिब में प्राचीन शस्त्र पाए गए हैं। तख्त साहिब के वास्तुशिल्प में एक बड़ा भवन निर्मित किया है एवं इमारत के सामने एक खूबसूरत वाटिका है। गुरुद्वारा के दर्शन करने भटिंडा से लेकर बर्मिधम के निवासी इस स्थल के दर्शन करने आते हैं। मार्च के महीने में होला मोहल्ला एवं बैसाख के महीने में कई लोग इस त्योहार को मनाते हैं। अप्रैल महीने में बैसाख का त्योहार धूमधाम एवं खुशियों से मनाया जाता है। होला मोहल्ला त्योहार दसवें गुरु गोबिंद सिंहजी ने मनाया है। हजारों श्रद्धालु यहाँ एकत्र होते हैं। रंगबिरंगे गुलाल के खेल में मन भाव विभोर हो जाता है। सन् 1999 में मनाया गया बैसाख पर खालसा पंथ के 300 साल पूरे हुए। पंजाब के प्रसिद्ध नृत्य-संगीत से त्योहार का प्रारम्भ होता है।



धरती का स्वर्ग है मॉरीशस

मॉरीशस के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो धरती से स्वर्ग में आ गए हों। मॉरीशस की मुद्रा रुपी है परन्तु यूरोप के पर्यटकों के लिए वस्तुओं की कीमत यूरो में होगी। इस द्वीप में सफर करने केलिए मई से दिसंबर तक का समय उपयुक्त है। इस क्षेत्र की प्रमुख भाषा क्रियोल है। अन्य भाषाएँ जो यहाँ प्रचलित हैं, वे है अँग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, क्रियोल। पोर्ट लुईस मॉरीशस की राजधानी है। अन्य मुख्य शहर हैं मोका, क्योरपाइप, वाकोस, फोइनक्स, क्राउरे बोर्नस, रोस हिल, बिउ

बासिन। मॉरीशस का क्षेत्रफल 330 वर्ग किलोमीटर है तथा आसपास समुद्री किनारे हैं। समुद्र के किनारे कोरल रीफ(समुद्र के पास पाया जाने वाला एक विशेष पौधा) से घिरे हुए हैं। समुद्र के किनारे मनोरंजन की सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

विभिन्न प्रकार की जलीय क्रीड़ाएँ खेल पर्यटकों के मध्य लोकप्रिय हैं जैसे वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइंग, पैरासेलिंग, सबमैरीन डाइव, जल स्कूटर, राइडिंग, ट्यूब राइडिंग, वोट सेलिंग आदि। पोर्ट लुईस एक प्रमुख व्यापारिक तथा पर्यटक स्थल है। इस

शहर में घूमने के लिए आप बाल्टर बीच(पुल) पर टहल सकते हैं। इस बीच का प्राकृतिक सौन्दर्य मनभावन है। थोड़ी ही दूर में वालंटियर प्वाइंट पर्यटक स्थल है। मॉरीशस में मोका एक प्रमुख शहर है। यहाँ पर आप महात्मा गाँधी इंस्टीट्यूट देख सकते हैं।

रोस हिल - इस शहर में खरीदारी के लिए माल्स, अरब टाउन मार्केट तथा टाउन सेंटर बाज़ार प्रसिद्ध हैं। क्योरपाइप - यह शहर शॉपिंग तथा भारतीय वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। बॉटैनिकल गार्डन्स तथा ट्राउ और सर्फस क्रेटर अब पर्यटक स्थल के

रूप में लोकप्रिय हैं।

माहेबर्ग में नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर नाट्टी डेम देस एंगेस (चर्च) प्रसिद्ध स्थल है। मॉरीशस में हस्तशिल्प बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कला काफी सालों से चलती आ रही है।

पैपलमाउसेस - यहाँ का शुगर एडवेंचर म्यूजियम बहुत ही मशहूर है। इस म्यूजियम में मॉरीशस के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक जानकारीयाँ उपलब्ध हैं।

कासेला बर्ड पार्क - ब्लैक नदी के पास स्थित यह पार्क 20 किलोमीटर जमीन पर स्थित है।

लाकशन



पांच केदारों में प्रमुख है मदमहेश्वर

पिठले साल मेरा कार्यक्रम मदमहेश्वर जाने का बना। मध्य

नवंबर तक यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर के कपाट बंद हो चुके थे। बस बद्रीनाथ और मदमहेश्वर के कपाट खुले थे। मैं निकला तो बद्रीनाथ के लिए ही था लेकिन रुद्रप्रयाग पहुंचकर बुद्धि फिरी और मदमहेश्वर जाने लगा। वहां जाने के लिए रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ तक जाना होता है। रुद्रप्रयाग से बसें और जीपें मिलती हैं। ऊखीमठ में मुख्य बाजार से सीधा रास्ता उनियाना जाता है जो आजकल मदमहेश्वर यात्रा का आधार स्थल है। मैं शाम तक उनियाना पहुंच गया था। यहाँ से मदमहेश्वर की दूरी 23 किलोमीटर है जो पैदल नापी जाती है। यूं तो मैं कभी अपनी यात्राओं में गाइड का सहारा नहीं लेता हूँ लेकिन इस बार लेना पड़ गया। चार सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तय किया था और आने-जाने का तीन दिन का हिसाब था। वैसे रास्ता इतना बढिया है कि गाइड की जरूरत ना पड़े। वैसे कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पहाड़ के सफर में कोई स्थानीय जानकार होना अच्छा रहता है। खास तौर पर किसी मुश्किल या प्राकृतिक संकट के वक़्त गाइड खासे काम आते हैं। अगले दिन सुबह उनियाना से चलकर तीन किलोमीटर आगे रांसी गांव पहुंचे। कुछ साल पहले तक यह यात्रा मनसूना से शुरू होती थी। मनसूना ऊखीमठ और उनियाना के बीच में है। तब यात्री पैदल ही मनसूना से उनियाना तक पहुंचते थे। अब उनियाना तक तो सड़क पहुंच गई है, आगे भी जाएगी। रांसी के लिए भी सड़क मार्ग पर बस एक पुल बनना बाकी है, सड़क बन चुकी है। जिस दिन पुल चालू हुआ, गाडियां उनियाना के बजाय रांसी तक जाया करेंगी। इस तरह पैदल चलने का रास्ता और कम हो जाएगा। वैसे भी रांसी उनियाना के मुकाबले ज्यादा समृद्ध और बड़ा गांव है। यहां राकेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर भी है। रांसी से हल्की सी चढ़ाई के बाद सामने दिखाई देता है गौण्डार गांव। गौण्डार तक सीधा ढलान है। घने जंगलों से होकर वहां तक पगडंडियां जाती हैं। यह इस घाटी का आखिरी गांव है। रांसी और गौण्डार के बीच में जो जंगल है, उसमें कई झरने भी हैं। दोपहर तक हम गौण्डार पहुंच गए। वहीं खाना खाया। उनियाना से अभी तक तो रास्ता कुल मिलाकर चढ़ाई भरा था लेकिन इतनी तेज चढ़ाई नहीं थी। असली चढ़ाई शुरू होती है गौण्डार से एक खड्ड को पार कर लेने के बाद। खड्ड के बाद सबसे पहले आती है बनतोली चट्टी। यहां रुकने का ठीकठाक इंतजाम है। यहां से चौखंभा चोटी के भी दर्शन होते हैं। वैसे तो चौखंभा उनियाना से निकलते ही दिखाई देने लगती है लेकिन बनतोली में उसे नजदीक से देखना रोमांचक है। गौण्डार से करीब डेढ़ किलोमीटर आगे आती है- खटया चट्टी।



करें आर्कटिक की सैर

सभी के मन में उत्सुकता रहती है कि आर्कटिक में कितनी ठंड होगी, कितनी बर्फ गिरती होगी, लोग कैसे रहते होंगे, वे क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पैदावार होती होगी आदि-आदि। इन्हीं जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमने वहाँ की यात्रा करने का निश्चय किया। सैलिब्रिटी क़रूजेज की यह यात्रा बारह दिनों की थी तथा एम्सरटडम (नीदरलैंड) से शुरू हुई। यात्रा सेन्चुरी जहाज से शुरू हुई। यह जहाज चौदह मंजिला है। यह यात्रा नावें के समुद्र तट के साथ चलते हुए आर्कटिक सर्कल को पार करते हुए नॉर्थ केप पहुँची। समुद्र किनारे पर सैकड़ों स्थानों पर समुद्र पृथ्वी के अंदर तक पहुँच जाता है। कहीं-कहीं तो यह मौलों तक होता है। ये रास्ते ऊँचे पहाड़ों से भारी ग्लेशियरों के तेज प्रवाह के कारण सैकड़ों वर्षों से बनते आ रहे हैं। इन्हें पयूई कहते हैं। इन पयूईस में गिरेनार पयूई, हारडेनार पयूई, नार्ड पयूई तथा सोगने पयूई काफी बड़े एवं दर्शनीय हैं। तीसरे दिन सुबह एलसंड पहुंचे। नावें के उत्तर-पश्चिम समुद्र तट पर बसा यह शहर इस देश का सबसे बड़ा मछली उत्पादक स्थान है। यहाँ सन्तमोर म्यूजियम, मार्बल चर्च, अटलांटिक सी पार्क दर्शनीय स्थल हैं। दिनभर यहाँ सैर करने के पश्चात शाम को जहाज आगे की यात्रा के लिए चल दिया। अगले दिन हम लोग समुद्र में ही रहे।

पीएम मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर जताया गहरा शोक

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अभिनेता को अंतिम विदाई दी। पीएम मोदी ने उनके अभिनय की गहराई, विविधता और हिंदी व मराठी सिनेमा में उनके योगदान की सराहना की। नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। निधन के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य राजनेताओं सहित अनेक लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, बहुत कम अभिनेताओं में वह गहराई, विशिष्टता और दमदार उपस्थिति थी जो नाना पाटेकर में थी। उन्होंने हर भूमिका में अद्भुत विविधता और रचनात्मकता का परिचय दिया और हमें ऐसे किरदार दिए जिन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। उनके निधन से एक बड़ी रिक्तता पैदा हो गई है। उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।

ईसी विरोध पर भाजपा अध्यक्ष नितिन ने राहुल गांधी को घेरा

वाराणसी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर अराजक मानसिकता रखने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नवीन ने चुनाव आयोग की आलोचना करने पर राहुल गांधी से सवाल किया और कहा कि इसी चुनाव आयोग ने केरल और तमिलनाडु में चुनाव कराए थे। मीडिया के मुताबिक, नवीन ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है, तो राहुल गांधी को सबसे पहले अपना इस्तीफा देना चाहिए! उन्होंने गांधी पर घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप भी लगाया और कहा कि उन्हें देश के संसाधनों, संपत्ति और जमीन पर अधिकार दिलाने की सभी प्रक्रियाओं को सेंट्रलाइज (एक जगह से नियंत्रित) करने के लिए बनाया गया था।

13 करोड़ वोटर लिस्ट में जुड़ने तक जारी रहेगी लड़ाई

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गुरुवार को कहा कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक वोटर लिस्ट में 13 करोड़ नाम वापस नहीं जोड़ दिए जाते। इस मामले पर बात करते हुए मसूद ने चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी संख्या खुद बांग्लादेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इमरान मसूद ने कहा कि जब तक यह लूट बंद नहीं होती और जिन 13 करोड़ लोगों के वोटिंग अधिकार छीने गए हैं, उन्हें वापस नहीं दिया जाता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। अगर इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटा दिए जाएं, तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है? बांग्लादेशी बताकर हटाए गए नामों की संख्या खुद बांग्लादेश की आबादी से भी ज्यादा है। फिर चुनाव आयोग का क्या मतलब है ?

हार का ठीकरा फोड़कर अराजकता फैला रहे राहुल

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे पार्टी की लगातार चुनावी हार के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराकर अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम यादव ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता अपनी राजनीतिक चालों से प्रधानमंत्री का सम्मान कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी जो अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। चुनाव आयोग की देखरेख में पूरी चुनावी प्रक्रिया होती है और कांग्रेस पार्टी को लगातार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है; ऐसे में अगर वे अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं, तो यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

बागी तृणमूल सांसदों ने जवाब के लिए 15 दिन का समय मांगा

कोलकाता। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बृहस्पतिवार को कहा कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के साथ जुड़ने वाले तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने दलबदल रोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिका पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब नोटिस का जवाब भेजने के लिए दी गई समयसीमा आठ अक्टूबर को समाप्त हो गई है। बागी सांसदों में शामिल घोष दस्तीदार ने कहा कि सांसद अब तक जवाब तैयार करने के लिए जरूरी सभी दस्तावेज इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन्होंने लोकसभा सचिवालय से और समय देने का अनुरोध किया है। घोष दस्तीदार ने मीडिया को बताया, “जवाब भेजने की हमारी समय-सीमा गुरुवार को खत्म हो गई है। हमने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर 15 दिन का और समय देने का अनुरोध किया है।” लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को तय समय-सीमा के भीतर जवाब देने के लिए आठ अक्टूबर तक का समय दिया था।

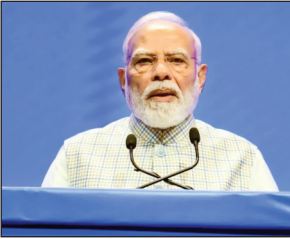
मुफ्त की कमाई बंद हुई तो चीखते रहें : पीएम मोदी

साइबर फ्रॉड पर ग्लोबल फ्रेमवर्क जरूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का गुरुवार को उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10 बजे यशोभूमि पहुंचे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री को स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभागार में मौजूद व्यक्तियों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने नाना पाटेकर को भी याद किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई, वे मोदी को प्यार करेंगे क्या? वे कितना भी चीखते-चिल्लाते रहें, मैं यह काम करता रहूंगा। अगर पुरानी व्यवस्था होती तो पांच लाख करोड़ रुपये लीकेज में चले जाते, लेकिन मोदी ने इसे रोका है। अब यह पैसा सही काम में लग रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत चार लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा किए जा चुके हैं। यह राशि हर कार महीने में किसानों तक पहुंचती है और ऐसे लोगों तक जाती है, जहां पहले कभी पैसा नहीं पहुंचता था।

पीएम मोदी ने कहा कि मोबाइल फोन ने भारत में कंटेंट क्रिएशन में क्रांति ला दी है, लेकिन फोन और नेटवर्क की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल की भाषा में नहीं



सोचता। जब उसके पास फोन आए तो उसे पता होना चाहिए कि कौन फोन कर रहा है। जब वह पेमेंट करे तो उसे भरोसा होना चाहिए कि उसका पैसा सुरक्षित है और उसका डेटा भी सुरक्षित है। साइबर फ्रॉड सीमाओं को नहीं मानते। एक देश में बैठा व्यक्ति दूसरे देश की मदद से तीसरे देश में अपराध कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत भाषा और भूगोल के लिहाज से विविधता वाला देश है। इसकी वजह से लोगों के जीवन में कई तरह की असुविधाएं भी आती हैं। मोबाइल ने इस विविधता को सुविधा से जोड़ने का काम किया है। पहले बैंक, अस्पताल और सरकारी दफ्तर शहरों में होते थे, जिससे गांव के लोगों का समय खर्च होता था। आज सरकार की सैकड़ों सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध हैं। डीबीटी के जरिए पैसा सीधे लोगों के खातों में जा रहा है

और पांच लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचे हैं।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम ‘स्कैल विदाउट बाउंड्रीज’ यानी बिना सीमाओं के विस्तार रखी गई है। इस आयोजन में भारत के दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी क्षेत्र में हुए विकास को दुनिया के सामने रखा जा रहा है। कार्यक्रम सरकार, दूरसंचार कंपनियों, तकनीकी विशेषज्ञों, स्टार्टअप और निवेशकों को एक मंच पर ला रहा है।

इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5जी और 6जी, अगली पीढ़ी के एआई नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, उपग्रह आधारित नेटवर्क, साइबर सुरक्षा और क्रांटम कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान रहेगा। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, डिजिटल ढांचे और तकनीक के कारोबारी इस्तेमाल से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी ने शिक्षा, भुगतान और स्वास्थ्य सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखने में मदद की। आज सुदूर गांवों और गरीब परिवारों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान 2022 तक दीक्षा मंच पर 500 करोड़ से ज्यादा सीखने के सत्र दर्ज किए गए।

स्टेल प्रमुख समाचार

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मैच आज

रांची। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। पहले मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम को नजर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने पर है, जबकि वेस्टइंडीज सीरीज में वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगा। हालांकि टीम प्रबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल सलामी जोड़ी को लेकर है, जहां संजू सैमसन और युवा वैभव सूर्यवंशी में से किसी एक को लेकर फैसला किया जा सकता है। भारतीय टीम के लगभग सभी प्रमुख बल्लेबाज इस समय अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन संजू सैमसन का बल्लेखामोश है। वह अपनी पिछली चार टी20 पारियों में सिर्फ 29 रन बना पाए हैं और इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर महज 11 रन रहा है। उनकी असफलता के कारण भारत को पारी की शुरुआत में अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है, हालांकि मध्यक्रम ने इसकी भरपाई की है।

पहले टी20 में कसान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टी20 करियर का पहला शतक लगाया। अपने 68वें टी20 मुकाबले में अय्यर ने शतकीय पारी खेलकर मध्यक्रम को मजबूती दी और सैमसन की नाकामी का असर टीम के प्रदर्शन पर नहीं पड़ने दिया। भारत ने वेस्टइंडीज के 171 रन के स्कोर को आसानी से पीछे छोड़ दिया। ऐसे में टीम प्रबंधन युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने का मौका दे सकता है। 15 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक मिले मौकों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित किया है। उनके पास कई तरह के शॉट हैं और वह पावरप्ले में तेजी से रन बनाकर विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में वुडि की घोषणा बटोरी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें अभी निरंतरता साबित करनी बाकी है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1045 अंक गिरा, निफ्टी साल के सबसे निचले स्तर पर बंद

मुंबई। वैश्विक बाजारों से मिले खराब संकेतों और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी कोहराम मच गया। चौतरफा बिकवाली के दबाव में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इस गिरावट के कारण एनएसई निफ्टी ने साल 2026 का अपना खराबे निचला स्तर छू लिया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 1,045.46 अंक या 1.44 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 71,593.24 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 371.25 अंक या 1.64 प्रतिशत टूटकर 22,231.80 पर सेटल हुआ। इंट्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान निफ्टी फिसलकर 22,179.90 के स्तर तक चला गया था, जो इस साल का इसका सबसे निचला स्तर है।

पीएनबी-बीओबी समेत कई बैंकों ने महंगा किया लोन

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद देश के कई बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बड़े बैंकों ने रेपो से जुड़ी अपनी बेंचमार्क लेंडिंग्स में 0.25 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। इससे इन बैंकों से लोन लेने वाले ग्राहकों की ईएमआई बढ़ सकती है। आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया। करीब चार साल बाद रेपो रेट में यह पहली बढ़ोतरी है। पीएनबी ने शेयर बाजार को भी जानकारी में बताया कि रेपो रेट बढ़ने के बाद उसने रेपो लिंकड लेंडिंग रेट को 8.10% से बढ़ाकर 8.35% कर दिया है। नई दर 8 अक्टूबर से लागू हो गई।

5जी ग्राहकों की संख्या 2030 तक एक अरब करने का लक्ष्य

नई दिल्ली। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत के 5जी ग्राहकों की संख्या मौजूदा 55 करोड़ से दोगुना कर 2030 तक एक अरब करने का है। उन्होंने कहा कि देश 6जी के मामले में दुनिया से पीछे था लेकिन उसने 4जी में दुनिया की अगुवाई करने का संकल्प लिया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में सिंधिया ने कहा कि भारत में 5जी दुनिया में सबसे तेजी से अपनाई जाने वाली 5जी प्रौद्योगिकी बन गई है। उन्होंने कहा, आज हमारे पास 5जी के 55 करोड़ उपयोगकर्ता हैं... लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे। 2030 तक हमारा लक्ष्य 5जी उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर एक अरब करना है। वहीं 6जी के बारे में सिंधिया ने कहा कि भारत के 6जी गठबंधन में 90 संस्थान शामिल हैं और उसने 7,700 पेटेंट हासिल किए हैं, जिनमें 4,400 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट हैं।

यूपीआई एमडीआर, 1 जनवरी से लागू होने की संभावना

नई दिल्ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के लेनदेन पर मचेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने की तारीख 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 1 जनवरी, 2027 किए जाने की संभावना है। इस मामले में वित्त मंत्रालय के साथ भी बातचीत चल रही है। अगर ऐसा होता है, तो क्रिसमस तक चलने वाले त्योहारों सीजन में यूपीआई भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के नेतृत्व वाली यूपीआई और सर्विसेज संचालन समिति के सदस्यों ने आज एमडीआर लागू करने की तारीख के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। हालांकि, अंतिम निर्णय को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा, सालाना 40 लाख रुपए तक कारोबार करने वाले कारोबारियों को एमडीआर से छूट देने के प्रस्ताव पर भी फैसला होने की संभावना है।

भारत में ब्याज दरों में बढ़ौतरी का चक्र प्रारम्भ

प्रह्लाद सबनानी

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 7 अक्टूबर 2026 को घोषित अपनी मौद्रिक नीति (मोनेटरी पॉलिसी) के माध्यम से रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि करते हुए इसे 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया है। भारत में, फरवरी 2023 के पश्चात, प्रथम बार रेपो दर में वृद्धि की घोषणा की गई है। अब संभवतः समस्त बैंक अपने ग्राहकों पर ब्याज दरों में बढ़ौतरी की घोषणा करेंगे। दरअसल, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी मुद्रा स्फीति की दर में वृद्धि देखी जा रही है और मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि देश पहिले से ही ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा कर चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भी मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रेपो दर में वृद्धि करने के अतिरिक्त और कोई उपाय था भी

नहीं। रेपो दर में वृद्धि वित्तीय बाजार में लगाए जा रहे अनुमान के आधार पर ही रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि निकट भविष्य में रेपो दर में कमी की सम्भावना अब कम ही है बल्कि वित्तीय बाजार का अनुमान है कि दिसम्बर माह में होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक में भी संभवतः रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की पुनः वृद्धि की घोषणा की जाएगी। दरअसल वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हम्यास युद्ध, ईरान-अमेरिका युद्ध तो लम्बे समय से चल ही रहा था अब सऊदी अरब-हुथी युद्ध भी छिड़ गया है एवं इसमें पाकिस्तान एवं टर्की भी शामिल हो गए हैं। इस सबका विपरीत प्रभाव वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का आपूर्ति पर पड़ा है एवं कच्चे तेल की कीमतें



आसमान छूने लगी हैं जिससे विश्व के कई देशों में मुद्रा स्फीति की स्थिति लगातार गम्भीर होती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत में मुद्रा स्फीति के अनुमान को बढ़ाया है। पूर्व में, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत में मुद्रा स्फीति के 5 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया गया है। मुद्रा स्फीति, एक गम्भीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है, इसे नियंत्रित करना अति आवश्यक है क्योंकि इसका सबसे अधिक विपरीत प्रभाव गरीब नागरिकों पर अति गम्भीर रूप से पड़ता है। मुद्रा स्फीति के

लगातार बढ़ने से नागरिकों की क्रय शक्ति कमजोर हो जाती है। पूरे विश्व में लगभग समस्त देशों द्वारा मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है ताकि नागरिक अपने खर्चों को बढ़ाने के लिए निरुत्साहित हों एवं इस धनराशि को वे बैंकों में जमा करें एवं साथ ही नागरिक बैंकों के ब्याज दर के बढ़ाने से ग्राहराशि पर अब अधिक ब्याज देना होगा। इससे बाजार में उत्पादों की मांग में कमी आती है एवं उत्पादों की कीमतें कम होने लगती हैं और अंततः मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण स्थापित होने लगता है। परंतु, ब्याज दरों में एक सीमा से अधिक वृद्धि करने से आर्थिक विकास दर विपरीत रूप से प्रभावित होने लगती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तो मुद्रा स्फीति का पछेय ही नहीं मिलता है क्योंकि उत्पादों की अत्यंत आपूर्ति बाजार में बनाए रखी जाती थी,

बल्कि शास्त्रों में उत्पादों के दाम कम होते जाने का उल्लेख जरूर मिलता है। वर्तमान स्थिति बिल्कुल भिन्न है, बाजार में उत्पादों की मांग बढ़ जाती है परंतु आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती है, इससे इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि दृष्टिगोचर होने लगती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि रेपो दर में की गई वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना लगभग शून्य है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि दर को संशोधित कर इसे पूर्व के अनुमान 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया गया है। अन्यथा, सामान्यतः ब्याज दरों में वृद्धि का आर्थिक विकास दर पर विपरीत प्रभाव दिखाई देता है। भारत में आर्थिक विकास दर मजबूत बनी हुई है।

23 विकास कार्यों का भूमिपूजन, आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य का लोकार्पण

मातृशक्ति के सम्मान और स्वावलंबन का मजबूत आधार बनी महतारी वंदन योजना : विष्णु देव

दुर्ग। छत्तीसगढ़ की लाखों माताओं-बहनों के आर्थिक स्वावलंबन, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत कर रही महतारी वंदन योजना ने आज एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में योजना की 32वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 67 लाख 38 हजार 217 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 632 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के अंतर्गत माताओं-बहनों को अब तक दी गई आर्थिक सहायता की राशि 20708 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और उनका आर्थिक सशक्तीकरण हमारी सरकार के लिए केवल एक योजना या कार्यक्रम नहीं, बल्कि सुशासन की प्रमुख प्रार्थमिकता है। हमारा विश्वास है कि जब परिवार की महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है।



बच्चों की शिक्षा और पोषण से लेकर परिवार के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े निर्णयों तक उसकी भागीदारी और मजबूत होती है। इसलिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार माताओं-बहनों के हाथों में आर्थिक सामर्थ्य देकर उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास दे रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नारीशक्ति को विकास की धुरी बनाते हुए महिला सशक्तीकरण को नई दिशा दी है। उनके नेतृत्व में महिलाओं के

सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक ऐतिहासिक पहल हुई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी भावना के अनुरूप माताओं-बहनों के जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना इसी संकल्प का सशक्त उदाहरण है। प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि लाखों महिलाओं के लिए अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने का

भरोसेमंद आर्थिक आधार बनी है। कोई बहन इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई में कर रही है, कोई पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में, तो कोई अपनी छोटी-छोटी बचत और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में इसका उपयोग कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन की राशि केवल बैंक खातों में पहुंचने वाली आर्थिक सहायता नहीं है। यह माताओं-बहनों के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन को नई शक्ति देने वाली राशि है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की माताएं-बहनें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हों, बल्कि परिवार और समाज के निर्णयों में उनकी भागीदारी भी निरंतर बढ़े।

प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रभावी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। योजना की शुरुआत से सितंबर 2026 तक 31 किस्तों में महिलाओं को 20075 करोड़ 76 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी थी।

नक्सल प्रकरणों की वापसी के लिए प्रक्रिया में तेजी लाएं : विजय शर्मा

15 दिनों में जिला स्तरीय समितियों की बैठक करें : उप मुख्यमंत्री



रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में नक्सल प्रकरणों की वापसी, आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों तथा नक्सल हिंसा से प्रभावित जवानों एवं नागरिकों के परिवारों को दी जा रही सहायता की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नक्सल प्रकरणों में निरुद्ध एवं न्यायालयों में प्रक्रियाधीन लोगों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। गंभीर अपराध, जनहानि तथा गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य पात्र प्रकरणों की वापसी के लिए निर्धारित प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रकरणों की वापसी की कार्रवाई नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में सभी जिलों से प्राप्त प्रकरण वापसी संबंधी आवेदनों की जिलावार एवं प्रकरणवार

समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक प्रकरण की वर्तमान स्थिति और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने प्रकरण वापसी के लिए प्रस्तावित संपूर्ण प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसे जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित जिलों में जिला स्तरीय प्रकरण वापसी समितियों की बैठक अगले 15 दिनों के भीतर आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अन्य राज्यों में आत्मसमर्पण करने वाले छत्तीसगढ़ के निवासियों को वापस राज्य में लाने की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे व्यक्तियों की वापसी के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाए। राज्य लौटने वाले आत्मसमर्पित व्यक्तियों को पुनर्वास केंद्रों में रखकर उनकी रूचि एवं क्षमता के अनुरूप आजीविकाप्रकर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकें।

सुखदेव भगत पहुंचे बोधघाट परियोजना के डूबान क्षेत्र के आने वाले 56 गांव के ग्रामीणों के बीच

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सीडब्ल्यूसी मेंबर सांसद सुखदेव भगत बस्तर दौरे के दूसरे दिन वे दंतेवाड़ा पहुंचे जहां सर्वप्रथम उन्होंने बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी के दर्शन किए जिसके बाद दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शकील रिजवी के नेतृत्व में जगह-जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में कांग्रेस भवन पहुंच कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसके बाद वे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंते, सह प्रभारी एस.ए. सम्पत कुमार, जरिता लैतफ्लांग, विजय जांगिड़, एवं महामंत्री मलकीत सिंह गैदू के साथ दंतेवाड़ा के बारासूर के लिए



रवाना हुए, जहां उन्होंने बोधघाट परियोजना में प्रभावित हो रहे 56 गांव के हजारों ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी बात कांग्रेस आलाकमान और विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक पहुंचाने की बात कही, जिसके उपरांत प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत सातधार गये जहां

से होते हुए वे बोधघाट परियोजना के लिए प्रस्तावित बांध की जगह पर पहुंच कर अवलोकन किया। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी सहित प्रदेश पदाधिकारी सहित दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शकील रिजवी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

शारदीय नवरात्री पर महाराष्ट्र मंडल का दुर्गा दौड़ का आयोजन



रायपुर। महाराष्ट्र मंडल की छत्रपति शिवाजी महाराज कार्यक्रम आयोजन समिति पहली बार शारदीय नवरात्रि पर भगवा ध्वज लेकर शिवाजी महाराज के सम्मान में दुर्गा दौड़ का आयोजन करेगी। रायपुर शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में मंडल की विभिन्न समितियों व सभी 17 महिला केंद्रों के माध्यम से दुर्गा दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी आयुवर्ग के लोग शामिल होंगे। श्रीशिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान सांगली महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ मंडल की कार्यकारिणी, पदाधिकारियों व सभासदों के साथ हुई बैठक में इस आशय की घोषणा मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले ने की। उन्होंने कहा कि मंडल के सभी समितियों के पदाधिकारियों, सभासदों की दौड़ में उपस्थिति रहेगी।

अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें, गंभीरता और सक्रियता से दायित्वों का करें निर्वहन : साव

उप मुख्यमंत्री ने की विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा



रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में सरगुजा और सूरजपुर जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, जो योजनाओं के क्रियान्वयन तथा

विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। सरगुजा के कलेक्टर श्री अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल और सूरजपुर की कलेक्टर श्रीमती रेना जमील भी बैठक में मौजूद थीं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चारों विभागों के अधिकारियों से योजनाओं एवं विकास कार्यों की

प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने तथा कार्यों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, इसलिए अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

रेलवे ट्रैक के किनारे जमा कचरे की सफाई के लिए अभियान शुरू

रायपुर। रायपुर रेल मंडल में 1 से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है इसी कड़ी में स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत रायपुर रेल मंडल में 6 से 8 अक्टूबर तक रेलवे ट्रैकसाइड की सफाई के लिए विशेष तीन दिवसीय अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान के दौरान रेलवे ट्रैक के किनारे जमा कचरा, प्लास्टिक एवं स्कैप को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेवल क्रॉसिंग, गेट लॉज, केबिन तथा ट्रैक के किनारे स्थित रेल कर्मचारियों के आवासों के आसपास जमा कचरे की भी सफाई की जा रही है। ट्रैक की दृश्यता एवं सिग्नल की दृश्यता में बाधा डालने वाली अनावश्यक झाड़ियों एवं वनस्पतियों को हटाने का कार्य भी अभियान में शामिल है। चलती रेलगाडियों के निकट कार्य करते समय सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए संबंधित विभागों के समन्वय से सफाई कार्य किया जा रहा है। जहां आवश्यक हो, अधिक मात्रा में जमा कचरे को हटाने के लिए मशीनीकृत व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर के अलावा रेलवे ट्रैक रेलवे स्टेशनों के आसपास का वातावरण स्वच्छ एवं सुंदर दिखाई दे इस हेतु भरसक प्रयास किया जा रहे हैं साथ ही यात्रियों एवं आम जनों से निवेदन किया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर कचरा ना फेंके ट्रेन से यात्रा करते समय भी खिड़की से कचरा ना फेंके डस्टबिन का उपयोग करें।



पूंजीपति मित्रों के लोन राइट ऑफ हो रहे हैं : कांग्रेस

रायपुर। आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाए जाने के फैसले को आसमान छूती महंगाई, घटती आमदनी और न्यूनतम बचत की त्रासदी से जूझ रही मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों पर चौतरफा वार बताते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मोदी सरकार के अव्यावहारिक निर्णयों से आम जनता की कमर टूट गई है। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन, कार लोन, एजुकेशन और पर्सनल लोन की किश्तें बढ़ गई हैं। ट्रैक्टर, कृषि उपकरण और केसीसी लोन पर ब्याज का बोझ बढ़ा है। युवाओं के लिए अपना घर बनाने या छोटा व्यवसाय शुरू करने का सपना महंगा हो गया है। मोदी सरकार ने रेपो रेट बढ़ाकर राज्य के लाखों लोन धारकों पर ईएमआई का नया बोझ डाल दिया है। साय सरकार राज्य में विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ का किसान, युवा और मध्यम वर्ग बैंक की किश्तें चुकाने में नीलाम हो रहा है। यह सरकार केवल चंद उद्योगपतियों का कर्ज माफ करती है और आम जनता पर ब्याज का बोझ थोपती है।



प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद

फॉर्च्यून मैदा के संबंधित बैच की बिक्री व वितरण पर तत्काल रोक

रायपुर। राज्य सरकार आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की सघन निगरानी की जा रही है। खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, खाद्य सामग्री के नमूनों का संकलन और प्रयोगशाला जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के माध्यम से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य हितों की रक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। विष्णु के सुशासन में जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जांच में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में फॉर्च्यून मैदा के संबंधित बैच की बिक्री एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करें तथा प्रतिबंधित बैच के उत्पाद का विक्रय एवं वितरण नहीं करें।



भाजपा के राज में ढाई साल में सड़के बढ़हाल हो गई : कांग्रेस

रायपुर। पूरे प्रदेश में सड़कों की बढ़हाल स्थिति के लिए भाजपा की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा है कि सड़कों को प्रदेश के विकास की धमनी कहा जाता है, सरकार नई सड़के तो बना नहीं पा रही, पुराने सड़कों की मरम्मत जो नियमित प्रक्रिया है, वह भी पूरी तरह बंद है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का आधे से अधिक कार्यकाल गुजर चुका है लेकिन अभी तक केवल मंजूरी और स्वीकृति के फर्जी दावे से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। भाजपा के कुशासन में केवल भ्रष्टाचार का ही विकास हुआ है, सड़कों रखरखाव के जिम्मेदार अधिकारी मंत्रियों के परिजनों की तेरही के बंदोबस्त में रहे, आम जनता टैक्स चुकाकर भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। भाजपा के कुशासन में भ्रष्टाचार ही विकास है। शहरों से लेकर गांव सड़कों के गड्ढे तालाब बन चुके, नए पुन-पुलियों के स्लैब गिर रहे। उप मुख्यमंत्री जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है अपनी जिम्मेदारी से बचने तथा सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा कर रील बना रहे है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा है कि विगत पौने तीन साल में हजारों करोड़ पीडब्ल्यूडी को बजट आबंटन किया गया।



मतदाता सूची में नाम जुड़वाने विशेष अभियान शुरू

बिलासपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों एवं नए युवा मतदाताओं के पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पहली बार मतदान के पात्र बने युवाओं तथा अब तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा सके नागरिकों के नाम जोड़े जाएंगे। वह कार्य बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा घर-घर भ्रमण कर मतदाता सूची के निरंतर अद्यतनीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी की कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और सभी पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीयन सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सम्पन्न नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने और मतदाता सूची में अपना पंजीकरण विधिवत सुनिश्चित करने की अपील की है। मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करने के लिए ईसीआईनेट मोबाइल एप्प या वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म में 6 में ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने राष्ट्रीय चिंतन शिविर में किया राज्य का प्रतिनिधित्व

राष्ट्रीय मंच पर सराही गई छत्तीसगढ़ की पोषण पहलें

रायपुर। बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहलें नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-चिंतन शिविर में सराही गईं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी में आयोजित सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। दो दिवसीय शिविर में देशभर के महिला एवं बाल विकास मंत्री और विभागीय सचिव शामिल हो रहे हैं।

सम्मेलन में भारत सरकार की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, भारत सरकार के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार, मिशन वात्सल्य, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण से जुड़े विषयों पर विचार-



विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्यों के अनुभव साझा करना और महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर मंथन करना है। सम्मेलन के प्रथम सत्र में छत्तीसगढ़ के 'वजन ल्यूहार' की विशेष सराहना हुई। इस पहल के माध्यम से बच्चों के वजन और पोषण की स्थिति के प्रति परिवारों तथा समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। बच्चों की नियमित वृद्धि पर निगरानी और

कुपोषण में कमी लाने के प्रयासों में जनभागीदारी को जोड़ना इसकी प्रमुख विशेषता है।

राज्य के 'हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा' अभियान की भी सराहना की गई। अभियान के माध्यम से घरों और आंगन में मुनगा लगाने तथा इसके पोषण संबंधी महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने की यह पहल परिवारों और

समुदाय को सुपोषण के प्रयासों से जोड़ रही है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बाल गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए तैयार स्वास्थ्य प्लान और साप्ताहिक आहार चार्ट को भी सराहा गया। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई इन व्यवस्थाओं से बाल गृहों में उनकी देखभाल को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत इन पहलों से छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सामने आए। सम्मेलन के आगामी सत्रों में चारों प्रमुख विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। कार्यक्रम के दूसरे दिन, 9 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में शामिल होंगे।

बिलासपुर। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम वेदपरसदा स्थित मुख्यमंत्री डीएचडी स्कूल में आयोजित सेवा सेतु शिविर ग्रामीणों के लिए सुविधाओं और सौगातों का केंद्र बना। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी शामिल हुए। शिविर में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास पूर्णता प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, श्रम पंजीयन कार्ड और पेंशन स्वीकृति सहित विभिन्न योजनाओं



से ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचने वाली ग्रामीणों ने विभागीय योजनाओं की जानकारी ली और अपनी जरूरतों से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाया। पूर्व विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि सेवा सेतु शिविर

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे आमजन तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों और शासकीय सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना है।